नई दिल्ली

24 सितंबर, 2026 गुरूवार

मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 175

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

जहीर को धोनी की सलाह पर बनाया गया है कोच 07

संक्षिप्त वार्ता

एफईएमए के तहत कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 ठिकानों पर ईडी के छापे

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) के अधिग्रहण से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के तहत बुधवार को कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी के द्वारा यह कार्रवाई कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े लोगों और संस्थाओं के परिसरों पर की जा रही है।

ईडी के मुताबिक तलाशी संजय पसारी, राजीव पसारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला से जुड़े परिसरों के अलावा बीटीएल ईपीटी लिमिटेड, मंडाल व्यापार प्रा लिमिटेट, ट्रोलेक्स (इंडिया) प्रा लि, सीईएमएफआईएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड और महाबलेश्वर मर्चेन्ट प्रा लिमिटेड आदि से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि एमबीईसीएल का नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का स्त्रोत क्या था और रकम का किस तरह से आवागमन हुआ।

पीएम मोदी के साथ कैबिनेट मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर

बैठक में कामकाज की समीक्षा, अगले चरण की प्राथमिकताओं पर चर्चा की उम्मीद

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार 23 सितंबर से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ दो दिन का चिंतन शिविर करेंगे। यह बैठक नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में होगी और 24 सितंबर तक चलेगी। इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा, आगे की राह पर चर्चा और शासन के अगले चरण के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान किए जाने की उम्मीद है। पहले की कुछ बैठकों के उलट इस बार के सत्र में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे।

इस दो दिवसीय बैठक का समय काफी अहम माना जा रहा है। यह बैठक पीएम मोदी द्वारा अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ की गई अलग-अलग बैठकों के बाद हो रही है। बैठकों का यह क्रम मंत्रिपरिषद के विभिन्न स्तरों को शामिल करते हुए एक सुनियोजित प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, जिसमें अब कैबिनेट मंत्रियों के लिए उनकी अपनी समर्पित बैठक तय की गई है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक चिंतन शिविर पहले से चल रहे कामों का जायजा लेने, सरकार के अगले कदमों की योजना बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़े आगे के सुधारों और प्राथमिकताओं की पहचान करने पर केंद्रित होगा। चचाओं में सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गति, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी, मंत्रालयों के बीच समन्वय और शासन में सुधार के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि यह तय किया जा सके कि सरकारी पहल जमीनी स्तर पर नतीजों में बदलें।

केन्द्र सरकार के कामकाज में निभा रहा है बड़ी भूमिका

दो दिवसीय विचार-विमर्श कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रालयों में प्रगति का आकलन करने, अधिक समन्वय की जरुरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा, जो आने वाले समय में सरकार के काम को आकार दे सकती हैं। सेवा तीर्थ में यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब नया सरकारी परिसर पीएमओ और केंद्र सरकार के कामकाज में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

बढ़ती विकास दर और तेजी से बढ़ता निवेश, नयी गति से विकास कर रहा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के एक निजी होटल में प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित ह्यविकसित भारत - बढ़ता मध्यप्रदेश' कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कान्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश अब विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर दो अंकों में पहुंच गई है और रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक स्थिति बनी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अब वास्तविक प्रगति कर रहा है। प्रदेश की विकास दर टू-डिजिट में है और इस समय बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर है। बड़ी संख्या में निवेशक मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर भी तैयार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को अनुकूल वातावरण, आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाए। कॉन्क्लेव में प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और उपलब्ध संभावनाएं इसे निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बना रही हैं।

भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी वैश्विक सूची में

नई दिल्ली। भारत के शहर अब केवल देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र नहीं रह गए हैं. वैश्विक आर्थिक बदलाव की नई कहानी भी लिख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट में दुनिया के 57 उभरते शहरों में भारत के 46 शहर शामिल हैं। खास बात यह है, मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी इस सूची में शामिल हैं।

देश में त्यौहार से पहले बिजली संकट!

35 फीसदी बचा कोयले का स्टॉक

नई दिल्ली। त्यौहार से पहले जब बिजली खपत बढ़ जाती है ऐसे में देश बिजली संकट से जूझ रहा है। ऐसा सरकारी डाटा के आंकड़े से पता चला है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 40 फीसदी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के पास बहुत कम मात्रा में फ्यूल बचा है। दरअसल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डाटा से इस बात का पता चला है। इस डाटा के मुताबिक 19 सितंबर तक ऐसे पावर प्लांट जिनके पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है, उनकी संख्या 74 हो गई है। पंलांट्स के पास 35 फीसदी से भी कम कोयले का स्टॉक बचा है, जिससे केवल तीन दिन से भी कम समय तक बिजली पैदा हो सकती है। ये संख्या पिछले हफ्ते तक करीब 60 थी जो एक हफ्ते में ही तेजी से बढ़ गई है।

सरकारी आंकड़ों से खुलासा, मौसम गर्म होने से बिजली खपत हो रही ज्यादा

रिपोट्र्स के मुतबाकि अलनीनो के असर और मौसम के बदलते मिजाज के कारण ऐसा हो रहा है। इस पीक समय में बिजली की जरूरत भी ज्यादा ही पड़ रही है। अल नीनो और हीट वेव के कारण मौसम जरूरत से ज्यादा गर्म है। इसी की वजह से बिजली की खपत भी ज्यादा हो रही है और प्लांट में कोयले की कमी भी हो रही है। सरकारी डाटा के मुताबिक भारत में बिजली की अधिकतम जरूरत पिछले हफ्ते 230 गीगावाट से 250 गीगावाट के बीच रही तो वहीं मई में बिजली की अधिकतम मांग 270 .70 गीगावाट के अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गई थी।

खरीदना पड़ा महंगा कोयला

एनालिस्ट्स का कहना है कि पावर प्लांट के स्टॉक में कमी सप्लाई से जुड़ी किसी बुनियादी दिक्कत का संकेत नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक अस्थायी समस्या लगती है। सितंबर की शुरूआत में भारत के कोयला और रेलवे मंत्रालय ने कहा था कि अनिश्चित मानसून की स्थिति के चलते शिपमेंट पर काफी असर पड़ा था, जिसके बाद से ही वो पावर प्लांट में सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल और अगस्त के बीच रिन्यूएबल पावर का प्रोडक्शन करीब 21 फीसदी तक बढ़ा था, लेकिन क्लीन एनर्जी की सप्लाई में उतार-चढ़ाव की वजह से, चौबीसों घंटे बिजली की मांग को पूरा करने में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की भूमिका अहम बनी रही तो वहीं पिछले हफ्ते की रिपोर्ट में ये सामने आया कि अगस्त में भारत में बिजली उत्पादकों का कोयला आयात भी बढ़ गया था, ये अपने 15 महीने के स्तर से काफी ऊपर पहुंच गया था। इसके पीछे की वजह हीट वेव और गर्मी थी, ऐसे में जल-बिजली का उत्पादन कम हुआ और बिजली कंपनियों को महंगा कोयला खरीदना पड़ा।

राम मंदिर दान चोरी केस में 7000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल

चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आठों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में 7 हजार पन्नों से अधिक की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। विवेचक बुधवार सुबह बड़े-बड़े बक्सों में चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे, जिसमें आरोप पत्र के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट और बैंक की जमा पर्चियां भी मौजूद थीं। इस चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम न होने पर मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है।

दाखिल की गई इस चार्जशीट में कुल 173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें 105 बार चोरी होने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड की गई जांच में 803 चीजों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाया गया है, जबकि 86 कीमती चीजों की रसीद नहीं मिल सकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से कार, गहने और 79.85 लाख रुपये नकद बरामदगी का भी चार्जशीट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को जानकारी दी थी कि एसआईटी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर मूल्यवान चढ़ावे से संबंधित लगाए गए सभी आरोपों का गहन सत्यापन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के गिनती कक्ष के सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि गिनती प्रक्रिया में शामिल कुछ लोगों की मिलीभगत से कक्ष से नकदी को अनधिकृत रूप से निकालने या छिपाने के 105 मामले सामने आए थे।

सामने आ रही है तीखी प्रतिक्रियाएं

चार्जशीट और एसआईटी की रिपोर्ट में कुल आठ आरोपियों की पहचान की गई है, तथा उनके बैंक खातों में जमा उस रकम का पूरा ब्यौरा दिया गया है जिसका कोई स्पष्ट स्त्रोत नहीं मिल सका है। इसके साथ ही, उन सभी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है जिनमें चोरी का अवैध पैसा लगाया गया था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और अधिवक्ताओं द्वारा नाम शामिल न किए जाने पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

जुकरबर्ग की संपत्ति में एक दिन में 2.2 लाख करोड़ रुपए का हुआ इजाफा

नई दिल्ली। मेटा के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में करीब 25 अरब डॉलर यानी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए का भारी इजाफा हुआ है। इस रिकॉर्ड वृद्धि का मुख्य कारण मेटा के शेयर मूल्य में आई तेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मेटा के शेयर की कीमत करीब 11.4फीसदी बढ़ गई, जो अप्रैल 2025 के बाद कंपनी के शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। शेयरों में इस उछाल के बाद जुकरबर्ग की कुल संपत्ति बढ़कर करीब 253.6 अरब डॉलर यानी करीब 24.32 लाख करोड़ रुपए हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के शेयर में यह तेजी कंपनी की एआई रणनीति को लेकर निवेशकों के बढ़ते भरोसे का नतीजा है। मेटा ने हाल ही में अपना नया एआई असिस्टेंट म्यूज लॉन्च किया है। यह एक ऐसा एआई टूल है जो उपयोगकताओं के कई रोजमर्रा के काम कर सकता है, जैसे ईमेल भेजना, यात्रा की बुकिंग करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना और शॉपिंग करना।

अल नीनो का विकराल रूप: प्रशांत में तूफानों का तांडव, भारत में वर्षा संकट गहराया

नई दिल्ली। प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो अब विकराल रूप धारण करता दिख रहा है, जिसका असर वैश्विक मौसम पर स्पष्ट है। इससे प्रशांत क्षेत्र में अब तक कम से कम 17 शक्तिशाली तूफानों को जन्म दिया है, जिन्होंने जान-माल के साथ-साथ समुद्री व्यापार को भी अस्त-व्यस्त किया है। वहीं, भारत में इस मॉनसून सीजन में कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे कृषि और जल संसाधनों के लिए गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर का बढ़ता तापमान उष्णकटिबंधीय तूफानों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन गया है। इस साल जून में अपनी दस्तक के बाद से अल नीनो लगातार मजबूत हुआ है, जिससे समुद्र की गर्म सतह तूफानों को अद्वितीय ऊर्जा प्रदान कर रही है और उनकी तीव्रता व संख्या में वृद्धि हुई है। अगस्त माह में सिर्फ प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में कुल 12 चक्रवाती प्रणालियाँ विकसित हुईं। हांगकांग के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, 1961 के बाद किसी एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में तूफानों का बनना यह एक नया रिकॉर्ड है। इन तूफानों का कहर अप्रैल से अब तक प्रशांत क्षेत्र में 230 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। चीन को जुलाई में लगातार तीन बड़े तूफानों सहित कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे भारी तबाही हुई। अमेरिकी आँकड़ों के अनुसार, सिर्फ जुलाई में चीन में इन आपदाओं से करीब 8.5 अरब डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा, प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने एशिया-प्रशांत के कुछ व्यस्ततम बंदरगाहों पर जहाजों के समय पर नहीं पहुँचने और बढ़ती भीड़ की समस्याओं की सूचना दी है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ा है। प्रशांत में जहाँ तूफानों का सिलसिला जारी है, वहीं भारत में मॉनसून की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 1 जून से 18 सितंबर तक के आँकड़ों के अनुसार, देश के लगभग 43 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य से कम या अत्यधिक कम बारिश दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, बिहार में लगभग 37 प्रतिशत और राजस्थान में करीब 20 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इस कमी का सीधा असर खरीफ फसलों की पैदावार और करोड़ों किसानों की आय पर पड़ना तय है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में भी प्रशांत क्षेत्र में तूफानी गतिविधियाँ बनी रह सकती हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान और बदलते वायुमंडलीय हालात जापान सहित कई एशियाई देशों के लिए तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री व्यवधान का खतरा बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए, अल नीनो का असर मॉनसून की असमानता के रूप में सामने आ रहा है, इसलिए वर्षा के क्षेत्रीय वितरण और कृषि पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर लगातार नजर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

लद्दाख के लिए सवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने वांगचुक की पदयात्रा

नई दिल्ली। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बुधवार को लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को दोहराने के लिए 20 किमी की पदयात्रा करने वाले हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी। ये पदयात्रा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग में की जा रही है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कहते हैं इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए वह श्यामवैली में इकट्ठे हुए हैं। ये वही वैली है जो बटालिक के पास है, जिसमें कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों ने जानें दी और लोगों ने बिना वर्दी के भारत की रक्षा की।

संयुक्त राष्ट्र: 80 साल के इतिहास में पहली महिला महासचिव की उम्मीदें

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल को फिर सामने ला रही है, क्या दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन को पहली बार कोई महिला महासचिव मिल सकती है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को करीब 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक महासचिव का पद पुरुषों के पास ही रहा है। वर्ष 2027 से शुरू होने वाले नए कार्यकाल के लिए इस बार कई महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे लैंगिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा चर्चा में है। मौजूदा महासचिव अंतोनियो गुतारेस का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा, जिसके बाद नए महासचिव का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होना है। इस पद के लिए सात उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं, जिसमें कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिन्सपैन, इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, बारबाडोस की कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट और कांगो गणराज्य की इवोन ए-बाकी जैसी महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के राफेल ग्रोसी, सेनेगल के मैकी साल और नाइजीरिया के ओलारा ओटुनू भी दौड़ में हैं।

इन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और अनुभव संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद के लिए उन्हें मजबूत दावेदार बनाते हैं। महासचिव के चयन की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से शुरू होती है। परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद को किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाकर 193 सदस्यीय महासभा के पास भेजना होता है। महासभा औपचारिक रूप से महासचिव की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होने के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी शक्तियों की सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती है। उम्मीदवारों की स्थिति जानने के लिए सुरक्षा परिषद में अब तक तीन गोपनीय स्ट्रॉ पोल हो चुके हैं। इन मतदानों का उद्देश्य अंतिम फैसला करना नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के प्रति सदस्यों के समर्थन और आपत्ति का संकेत समझना है।

तीन स्ट्रॉ पोल के बाद भी उलझन बरकरार

रिपोर्टों के अनुसार, रेबेका ग्रिन्सपैन को शुरूआती दौर में मजबूत समर्थन मिला है, जबकि अन्य उम्मीदवार भी दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि अभी किसी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी ने इस चुनाव को लैंगिक प्रतिनिधित्व के नजरिए से भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यदि किसी महिला की नियुक्ति होती है तो वह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली महिला महासचिव होंगी। इससे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को लेकर लंबे समय से उठते सवालों को नया संदर्भ मिलेगा। अंतिम निर्णय सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया, स्थायी सदस्यों की सहमति और महासभा की औपचारिक नियुक्ति के बाद ही होगा।

संपादकीय

यूएन रुकवा सकेगा युद्ध ?

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों की बैठकें आरंभ हो रही हैं। युद्ध, शांति, स्थिरता महासभा के बुनियादी एजेंडे में शामिल हैं। हालांकि युद्ध तभी शांत और समाप्त हो सकते हैं, जब युद्धरत देशों में संवाद और समझौता हो सके। फिलहाल ऐसे आसार न तो रूस-यूक्रेन युद्ध और न ही ईरान युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की महत्ता, उसके आह्वान, उसकी मध्यस्थता और सामूहिक प्रासंगिकता खंडित, क्षीण हो चुके हैं, लिहाजा युद्ध भडक रहे हैं। आम आदमी मर रहा है या विस्थापन को विवश है अथवा भुखमरी-शरण का शिकार है। महासभा के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति टंप और यूक्रेन के आपातकालीन राष्ट्रपति जेलेंस्की के अतिरिक्त राष्ट्रपति टंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें और संवाद व्हाइट हाउस में होने हैं। जेलेंस्की को युद्ध रोकने को टंप बाध्य कर पाएंगे, इसके प्रथमद्रष्ट्या आसार नहीं हैं। टंप ने जेलेंस्की को फोन पर भी अपील की थी कि रूस के तेल ठिकानों, ऊर्जा-संयंत्रों, रिफाइनरियों पर हमले न किए जाएं। उससे वैश्विक संकट गहराता जाएगा। जेलेंस्की नहीं माने और एक साथ 1600 से अधिक ड्रोन दाग कर मॉस्को और आसपास के ऊर्जा-ठिकानों पर ही हमले कराए। यूक्रेन का रूस पर यह सबसे बड़ा और विनाशक हमला था। हालांकि रूस का दावा है कि उसके वायु रक्षा तंत्र ने 1110 ड्रोन हवा में ही मार गिराए, लेकिन 450 से अधिक ड्रोनों के हमले विध्वंसकारी, भस्मकारी, विनाशक साबित हुए। रूस का करीब 40 फीसदी रिफाइनिंग सिस्टम नष्ट हो चुका है।

भारत से पेट्रोल, डीजल खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल रूस ही सप्लाई कर रहा है। अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं है। राष्ट्रपति टंप का बयान आया है कि अब यह बेतुका युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि हर महीने 25,000 से ज्यादा लोग और सैनिक मर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध बेतुका है, तो ईरान में कौन-सा युद्ध जारी है? उस युद्ध को किसने जबरन थोपा था? राष्ट्रपति टंप शेष विश्व को मूर्ख और अज्ञानी न समझें। खौफनाक आंकड़े ये हैं कि साढ़े 4 साल से जारी युद्ध में रूस के करीब 3-4.5 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। कुछ रपटों में हताहत और घायल सैनिकों की संख्या 10 लाख से अधिक बताई गई है। यह मानवीय संहार की स्थिति है। स्वतंत्र और पश्चिमी संस्थाओं के अनुमान के मुताबिक, यूक्रेन के 1-1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की अक्सर ये आंकड़े करीब 46,000 से 55,000 के बीच मानते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, फरवरी, 2022 से जुलाई, 2026 तक यूक्रेन में कमोबेश 16,874 आम नागरिक मारे गए और 51,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन ने आधिकारिक रूप से हताहत सैनिकों और नागरिकों तथा विस्थापित लोगों के डाटा कभी नहीं दिए हैं, लिहाजा विभिन्न संस्थाओं के अनुमान ही मान्य हैं। सबसे खौफनाक, विनाशक, तबाही-बबार्दी के नतीजतन आने वाली सर्दियों में यूरोप और यूक्रेन किस कदर कांपते-ठिठुरते रहेंगे, इसका मानवीय अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस और दूसरी तरफ सऊदी अरब की पाइपलाइन फिलहाल खंडित अवस्था में हैं और गैस आपूर्ति करने में असहाय, असमर्थ हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहरों, स्टील और ऊर्जा के संयंत्रों में 70-90 फीसदी तक की तबाही बताई जा रही है। रूस के अत्यंत विनाशकारी, विध्वंसकारी हमले जारी हैं। दोनों देशों ने मिसाइल-ड्रोन हमले कर सैन्य गोदाम, कैंप, सप्लाई के भंडार, हथियार डिपो, लॉजिस्टिक सेंटर, मॉल और तेल-गैस ठिकानों पर ऐसे हमले किए हैं कि वजूद ही खत्म कर रहे हैं। न जाने इन देशों के पुनर्निर्माण कैसे संभव होंगे? राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी खंडहर देश के नेता साबित होना चाहते हैं क्या? रूस सबसे विशालकाय देश है। वहां स्टेट ड्यूमा (लोकसभा के समान) के चुनावों में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया को करीब 58 फीसदी वोट मिले हैं और उन्होंने 355 सीटें जीत कर फिर बहुमत हासिल किया है। बहरहाल लगभग सभी यूरोपीय देशों में तेल-गैस के संकट गहराते जा रहे हैं। तेल खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र, 193 देशों, खासकर राष्ट्रपति टंप और द्विपक्षीय संवाद करने वाले राष्ट्रपतियों से ही आखिरी उम्मीद और अपेक्षा है कि वे युद्ध रुकवाने में अपनी पूरी शक्ति, तमाम प्रभावों को झोंक दें।

अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों ?

हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढ़ना है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यही भारतीय अर्थव्यवस्था का सच है।

हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जीडीपी की गणना की प्रक्रिया को लेकर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कौनसे क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौनसा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो ब्लूमबर्ग और आरबीआई के अनुमानों से अधिक है। सरकार इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, जो ठीक है, हालांकि इन आंकड़ों पर सरकार में ही वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने सवाल उठाए, जिसने बहस छेड़ दी। फिर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कहा है कि पिछले साल के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन के कारण मौजूदा विकास दर वास्तविकता से अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर जीडीपी के आंकड़ों की तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यह विवाद मुख्य रूप से जीडीपी की तुलना के आधार यानी बेस ईयर डेटा को लेकर है। अगर सरकार कह रही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि अप्रैल से जून की मौजूदा तिमाही में भारत का कुल आर्थिक उत्पादन पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 7.8 फीसदी अधिक रहा। ये तिमाही के आंकड़े दरअसल एक अनुमान हैं। ये ग्रोथ का सटीक आकलन नहीं होता।

ये अनुमान इसलिए जारी होते हैं ताकि उसके हिसाब से बजट बने, पूरे देश में सालभर में हुई कमाई का असली आकलन करने में एक-डेढ़ साल लग जाता है। इस मुद्दे पर सवाल है कि अगर पिछले वर्ष का आधार आंकड़ा बदल गया है, तो नई वृद्धि दर को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि समय-समय पर आंकड़ों की गणना की पद्धति और आधार वर्ष बदलते रहते हैं, इसलिए संशोधित सिरीज के आधार पर ही तुलना उचित मानी जाती है। यह एक ठोस कारण है। हर सरकार अपने कार्यकाल में जीडीपी की गणना के मैथड और बेस ईयर को अपडेट करती है ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर बेहतर ढंग से सामने आ सके। ऐसा दुनियाभर में होता है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ये सभी चीजें भी बेहतर होंगी। लेकिन समस्या यह है कि पिछले 15 साल के दौरान भारत में जीडीपी लगातार बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बढ़ी है। इसके बावजूद रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं दिखी। और आम श्रमिकों और नियमित मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की आय भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह एक रिसर्च और खोज का बिन्दु है। भारत में जितनी भी वृद्धि हुई है, उससे यह साफ दिखाई देता है कि उसमें असमानता की बड़ी भूमिका है। पहले से संपन्न लोगों तक जीडीपी वृद्धि का बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है, जिनके पास पहले से पूंजी और संसाधन हैं, लाभ मुख्य रूप से उन्हीं के पास केंद्रित होता जा रहा है। इसके विपरीत, आम जनता, मजदूरों और किसानों तक उस वृद्धि का लाभ उसी अनुपात में नहीं पहुंच रहा। अमीरों के पास धन जाने से उसका लाभ अपने आप सभी तक पहुंच जाने से जुड़ा ह्यट्रिकल-डाउनह्ल सिद्धांत व्यावहारिक रूप से सफल नहीं रहा है।

इसके लिए मजदूरों और किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर अधिक निवेश करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है रोजगार और मजदूरी बढ़ाना, क्योंकि इससे लोगों की खरीद क्षमता और घरेलू मांग बढ़ती है। सरकार को वैश्विक चुनौतियों, जैसे युद्ध और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में संतुलन भी बनाना पड़ता है। उस व्यवस्था में बदलाव करना होगा जिसमें आर्थिक विकास का सबसे ज्यादा लाभ पहले से संपन्न लोगों को मिलता है। इसके बजाय मजदूरों, वेतनभोगी कर्मचारियों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नियमों और नीतियों में बदलाव किए जाएं। साथ ही सरकार बड़े पूंजीपतियों और अधिक संपन्न वर्ग पर टैक्स लगाकर उस संसाधन का उपयोग बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर करे। इन क्षेत्रों में निवेश करने से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पैदा होगा। इससे लोगों के हाथ में पैसा आता है, मांग बढ़ती है और जीवन स्तर बेहतर होता है। घरेलू स्तर पर मांग बढ़ाने से ही विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में नाजुक स्थिति में है और यह बात दुनिया भर के निवेशक भी समझते हैं।

देश के बड़े उद्योगपति खुद पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के भीतर मांग पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले घरेलू मांग बढ़ानी होगी। और मांग तब बढ़ती है जब लोगों के पास रोजगार हो और उनकी आय बढ़े। इसलिए रोजगार और वेतन वृद्धि, दोनों ही न केवल देश के अंदरूनी आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि वैश्विक निवेशकों के भरोसे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप व्यापक आर्थिक संकेतकों को देखें, तो विकास दर मजबूत है। राजकोषीय स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है और कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई देती है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढ़ना है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यह ही भारतीय अर्थव्यवस्था का काला सच है। असली विकास तब होगा, जब गरीब और अमीर के बीच आय अंतर बहुत कम हो जाएगा।

डा. वरिंद्र भाटिया, कालेज प्रिंसीपल

अब टाटा समूह पर सरकार की नजर

टाटा समूह भारत की शान है, लेकिन अब इस शान पर लगता है, जल्द ही बट्टा लगने जा रहा है। जिस तरह से टाटा की विरासत पर एक-एक करके हथौड़े मारे जा रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि टाटा समूह को हथियाने की कोशिश शुरू हो गई है। आधुनिक भारत के निर्माण में टाटा समूह का बहुत बड़ा योगदान है। इस पारसी परिवार ने भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। देश और विदेश में घूम-घूम कर तकनीकी के माध्यम से पारसी परिवर के सदस्यों ने भारत में उद्योग स्थापित किये। टाटा समूह विभिन्न उद्योगों के जरिए अपना रास्ता बनाता रहा। उसने कभी सरकारों का कोई सहारा नहीं लिया। टाटा समूह पूर्णता औद्योगिक संस्थान था। उसकी औद्योगिक गतिविधियों में जिस तरह से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और पूंजी के बल पर मजबूत संगठन तैयार किया। टाटा की पहचान को आज भी सारी दुनिया में एक विश्वास और प्रतीक के रूप में देखा जाता है। टाटा समूह की कभी भी राजनीतिक दलों और सरकारों की मनमर्जी से काम करने की प्रवृत्ति नहीं रही है। समय-समय पर जो भी नियम और कानून बने, उनका टाटा समूह ने अक्षरशः पालन किया। उद्योग और व्यापार में टाटा उद्योग की साख भारत ही नहीं पूरे विश्व में बनी। स्वतंत्र भारत के विकास में टाटा समूह ने स्टील, ट्रक, आटो मोबाइल, बिजली, इंजीनियरिंग, केमिकल इत्यादि के क्षेत्र में देश की जरूरत के हिसाब से अपने औद्योगिक साम्राज्य को बढ़ाया। इसके साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बेहतरी, उनके सुख-सुविधा, वेतन तथा कैंसर जैसी बीमारियों के लिए रिसर्च सेन्टर, हवाई जहाज एवं समाज सेवा में टाटा समूह ने समय-समय पर दिल खोलकर दान दिया। टाटा ने ऐसे संस्थान खड़े किए, जिससे टाटा समूह सारी दुनिया में एक औद्योगिक संस्थान के रूप में देखा गया। इसकी विश्वसनीयता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा।

टाटा ने ब्रिटेन में जगुआर लैंड रोवर, टाटा स्टील ने कोरस विदेश में खरीदा। टीसीएस ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। टाटा मोटर्स ने कार, ट्रक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने ब्रांड को विकसित किया। जहां टाटा का नाम आता था, वहां अपने आप लोगों के मन में विश्वास जाग जाता था, जो भी होगा अच्छा ही होगा। 2014 के बाद से देश में पूंजीवाद अपने चरम स्थिति पर जाते हुए दिखा। 1990 में पहली बार शेयर बाजार में गुजराती कारोबारियों की दखलअंदाजी बढी। देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में शेयर बाजार में एक तरह से सटोरिया और तेजड़ियों के रूप में गुजराती कारोबारियों की बड़ी तेजी के साथ सक्रियता बढ़ी। उसके बाद से पूंजीवाद और उद्योग व्यापार में अनैतिकता का खेल शुरू हो गया। 2014 के बाद से औद्योगिक संस्थानों एवं देश की सम्पत्ति पर कब्जा करने की साजिश शुरू हो गई। इस साजिश का शिकार अब टाटा समूह होने जा रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। रतन टाटा और मुकेश अंबानी ने गुजरात में पहली बार कहा था, भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के पास होना चाहिए। इसके बाद से वह गुजराती लॉबी के संपर्क में आए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से रतन टाटा का उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने करना शुरू कर दिया। रतन टाटा को पीएम केयर फंड में भी शामिल किया गया। भोले-भाले पारसी रतन टाटा इस कुचक्र को समझ नहीं पाए। धीरे-धीरे वह सत्ता एवं गुजराती लॉबी के चक्रव्यूह में फंसते चले गए।

देश और दुनिया में टाटा समूह की सबसे बड़ी पूंजी उसकी साख है। अब इस साख पर गुजराती कारोबारियों की नजर लग गई है। 2014 के बाद जिस तरह से लोकतंत्र की सभी संस्थाओं, सरकारी संस्थानों पर गुजराती बंधुओं का कब्जा हो रहा है। नौकरशाही, कार्यपालिका, मीडिया, न्यायपालिका में जिस तरह से गुजराती उद्योगपतियों का प्रवेश हुआ है, जिस तरह से कंपनियों एवं सत्ता पर अडानी-अंबानी का कब्जा सुनयोजित रूप से कराया जा रहा है। इसरो जैसी संस्था को भी अडानी के हवाले किया जा रहा है। क्रोनी पूंजीवाद का जो नंगा नाच जो भारत में हो रहा है, वैसा दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है।

अब टाटा समूह जैसी कंपनी में आंतरिक विवाद पैदा कराके उसे हथियाने की जो कोशिश की जा रही है। अब एनडीटीवी की भी याद आने लगी है। कैसे उसे जाल में फंसाकर सरकार और न्यायपालिका की सहायता से एनडीटीवी के प्रवर्तक को बाहर करके एनडीटीवी पर अडानी का कब्जा हो गया। कई अन्य उदाहरण भी हैं। अब उसी राह पर टाटा समूह को ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। संघ और भाजपा के बारे में एक कहावत यह भी है, यह जहां-जहां जाते हैं, वहां पर भाई-भाई में झगड़ा करा देते हैं। यही स्थिति अब टाटा समूह की होती हुए दिख रही है। कहा जा रहा है, टाटा समूह की जबसे सरकार से नजदीकी बढ़ी है, उसके बाद से टाटा समूह कमजोर होता चला जा रहा है। वर्तमान में सरकार और लोकतांत्रिक संस्थायें भी इस खेल में शामिल होती दिख रही हैं। टाटा समूह अपने-आपको बचा पाएगा, या साजिश का शिकार होगा, इसकी चर्चा होने लगी है।

(लेखक-सनत जैन)

शिक्षक पर हाथ उठाना समाज की हार

किसी विद्यालय के परिसर में यदि विद्यार्थी अपने प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट पर उतर आएं, तो उस घटना को केवल अनुशासनहीनता कहकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। यह घटना समाज के सामने एक अधिक गंभीर प्रश्न रखती है- क्या हमने असहमति को व्यक्त करने के लोकतांत्रिक तरीके खोने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट स्कूल में प्रधानाध्यापक के साथ हुई कथित मारपीट इसी प्रश्न को कठघरे में खड़ा करती है।

घटना के पीछे जो भी शिकायतें या आरोप रहे हों, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मिड-डे मील में अनियमितता अथवा किसी अन्य मामले को लेकर शिकायत थी, तो उसके लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध थी। आरोप सही पाए जाते तो नियमानुसार कार्रवाई होती। लेकिन किसी शिकायत की गंभीरता हिंसा को वैध नहीं बना देती। किसी व्यक्ति के दोषी होने का फैसला आरोप लगाने वाली भीड़ नहीं, विधिसम्मत प्रक्रिया करती है। यही सभ्य समाज और अराजक समाज के बीच की बुनियादी रेखा है।

यह बात शिक्षक के पक्ष में खड़े होकर नहीं, कानून के पक्ष में खड़े होकर कही जानी चाहिए। शिक्षक भी कानून से ऊपर नहीं है। वह गलती कर सकता है, अनुचित व्यवहार कर सकता है और उसके विरुद्ध शिकायत हो सकती है। लेकिन उसके विरुद्ध कार्रवाई का रास्ता भी वही होना चाहिए जो किसी अन्य नागरिक के लिए है- शिकायत, जांच, सुनवाई और नियमानुसार निर्णय। दूसरी ओर विद्यार्थी को भी यह समझना होगा कि अधिकार का अर्थ मनमानी नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी को प्रश्न करने का अधिकार है। वह शिक्षक के निर्णय से असहमत हो सकता है। वह प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। वह प्रशासन से जवाब मांग सकता है। लेकिन इन अधिकारों का अर्थ यह नहीं कि वह किसी शिक्षक को धमका सकता है या उस पर हाथ उठा सकता है। असहमति लोकतंत्र है, हिंसा अराजकता। आज हमारे समय की एक बड़ी विडंबना यही है कि हम बच्चों को स्वतंत्रता का अर्थ तो समझाना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी का संस्कार उतनी गंभीरता से नहीं दे पा रहे।

हम चाहते हैं कि बच्चे सवाल करें, लेकिन उन्हें यह भी बताना होगा कि सवाल का उत्तर मनचाहा न मिले तो अगला कदम क्या है। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं। लोकतंत्र का अर्थ है- असहमति के बावजूद व्यवस्था के भीतर समाधान खोजने की क्षमता। विद्यालय इस लोकतांत्रिक संस्कार की पहली पाठशाला है। इसलिए शिक्षक पर हमला केवल शिक्षक की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला नहीं है। यह विद्यालय के उस नैतिक वातावरण को भी चोट पहुंचाता है जिसमें बच्चों को तर्क, अनुशासन और संवाद सीखना है। बच्चे किताबों से जितना सीखते हैं, उससे कम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से नहीं सीखते। यदि उन्हें यह संदेश मिलता है कि ताकतवर व्यवहार से नियमों को बदला जा सकता है, तो कानून और संस्थाओं पर विश्वास का पाठ कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहां एक दूसरी सच्चाई को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षक का सम्मान अंध-समर्थन नहीं है। शिक्षक के हाथ में कक्षा का अधिकार है, समाज की निरंकुश सत्ता नहीं। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करे। अनुशासन के नाम पर अपमान, भय या अनुचित कठोरता स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि कोई शिक्षक अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध शिकायत होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। समस्या तब और बढ़ जाती है जब परिवार भी विवाद के समाधान का संस्थागत रास्ता छोडकर सीधे टकराव का रास्ता चुनने लगता है। बच्चे के साथ अन्याय हुआ हो तो अभिभावक का हस्तक्षेप स्वाभाविक और आवश्यक है। लेकिन बच्चे के प्रति प्रेम का अर्थ उसकी हर शिकायत को बिना जांच सत्य मान लेना नहीं है।

अभिभावक की भूमिका बच्चे का पक्ष लेने के साथ उसे जिम्मेदारी का अर्थ समझाने की भी है। यदि बच्चे को विद्यालय से शिकायत है, तो अभिभावक को विद्यालय प्रशासन से संवाद करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शिक्षा विभाग तक मामला ले जाना चाहिए। यदि कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक के साथ सार्वजनिक अपमान, धमकी या हिंसा को बच्चे के समर्थन का नाम नहीं दिया जा सकता। वास्तव में, आज हमें विद्यालयों में एक ऐसी शिकायत-व्यवस्था की आवश्यकता है जो विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक- तीनों का विश्वास जीत सके। विद्यार्थी को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी शिकायत दबाई नहीं जाएगी। शिक्षक को यह विश्वास होना चाहिए कि शिकायत के नाम पर उसे भीड़ के सामने असुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा। अभिभावक को भरोसा होना चाहिए कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा। जब संस्थाएं विश्वसनीय होती हैं, तब भीड़ की जरूरत कम हो जाती है। इस संदर्भ में प्रशासन की भूमिका निर्णायक है। विद्यालयों में नियमित संवाद, काउंसलिंग, शिकायत-निवारण तंत्र और संवेदनशील अनुशासन व्यवस्था को मजबूत करना अब वैकल्पिक कदम नहीं रह गया है। बच्चों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि हिंसा गलत है। उन्हें यह भी सिखाना होगा कि विवाद की स्थिति में सही रास्ता क्या है। इसी तरह शिक्षकों को भी बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। आज का विद्यार्थी पहले की तुलना में अधिक प्रश्न करता है, अधिक जानकारी रखता है और अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है। यह स्थिति शिक्षक के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए अवसर भी है। शिक्षक का अधिकार अब केवल पद से नहीं, संवाद और विश्वास से मजबूत होगा। यहां सोशल मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी घटना का वीडियो सामने आते ही समाज कई बार तथ्य और संदर्भ जाने बिना फैसला सुनाने लगता है। कुछ सेकंड के वीडियो से पूरी घटना का सत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। विद्यालय जैसी संवेदनशील जगहों पर किसी घटना को तमाशे या वायरल सामग्री में बदलने के बजाय तथ्यात्मक जांच और जिम्मेदार रिपोर्टिंग की जरूरत है।

डा. विजय विशाल, साहित्यकार

आलेख

दीपक की लौ और हमारी सांस्कृतिक संवेदना

आप दीप जलाते हैं या नहीं जलाते, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। किसी धार्मिक परंपरा को मानना, उससे दूरी रखना या अपने तरीके से उसका पालन करना—लोकतांत्रिक समाज में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन जब व्यक्तिगत पसंद या राजनीतिक असहमति की अभिव्यक्ति किसी धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक परंपरा के सार्वजनिक उपहास तक पहुँच जाती है, तब सवाल केवल एक दीपक का नहीं रह जाता। सवाल यह होता है कि असहमति जताते समय हम दूसरों की आस्था और सांस्कृतिक संवेदनाओं का कितना सम्मान करते हैं।

भारतीय संस्कृति में दीपक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दीपावली का पूरा भाव ही प्रकाश, आशा और अंधकार पर प्रकाश की विजय से जुड़ा है। घर, मंदिर और अनेक शुभ अवसरों पर दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। संध्या समय दीप जलाने की परंपरा भी अनेक भारतीय परिवारों में आज तक दिखाई देती है। इसलिए किसी के लिए दीप केवल तेल, बाती और मिट्टी से बनी वस्तु नहीं है; वह श्रद्धा, शुभता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है।

इसी भाव को संस्कृत की प्रसिद्ध प्रार्थना में व्यक्त किया गया है— ह्लदीपो ज्योतिः परं ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं, संध्यादीप नमोऽस्तुते।ह्व अर्थात दीपक की ज्योति को परम प्रकाश के रूप में नमन किया गया है और उससे अज्ञान तथा नकारात्मकता दूर होने की कामना की गई है। यही कारण है कि किसी सनातनी परिवार में दीप प्रज्ज्वलित होना केवल एक सामान्य घरेलू गतिविधि नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा संस्कार हो सकता है।

इसलिए दीप जलाना किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दीप जलाने वाले व्यक्ति की आस्था का मजाक उड़ाना भी उचित नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी पसंद की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि दूसरे की पसंद और आस्था के सम्मान की जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जब किसी धार्मिक प्रतीक को किसी राजनीतिक आयोजन से जोड़ दिया जाता है, तो उस आयोजन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति यह पूछ सकता है कि सार्वजनिक संस्थानों में किसी राजनीतिक कार्यक्रम की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसमें भागीदारी

स्वैच्छिक है या नहीं और सरकारी संसाधनों का उपयोग किस सीमा तक उचित है।

यहीं राजनीतिक आयोजन की आलोचना और सांस्कृतिक प्रतीक के अपमान के बीच अंतर करना जरूरी हो जाता है। यदि किसी कार्यक्रम में दीप जलाने को लेकर आपत्ति है, तो सवाल कार्यक्रम की राजनीतिक प्रकृति, प्रशासनिक भूमिका, खर्च या सहभागिता के तरीके पर होना चाहिए। स्वयं दीपक, पूजा या सनातन परंपरा को निशाना बनाना बहस को दूसरी दिशा में ले जाता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक आयोजन का विरोध करता है, तो केवल इस आधार पर उसे भारतीय संस्कृति या धर्म-विरोधी कहना भी उचित नहीं होगा।

आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इसके साथ एक समस्या भी आई है—व्यंग्य और आलोचना के बीच की सीमा कई बार धुंधली हो जाती है। कुछ शब्द या चित्र कुछ लोगों को सामान्य राजनीतिक व्यंग्य लग सकते हैं, लेकिन वही सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी आस्था का अपमान महसूस हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक संवेदनशीलता भी जरूरी है।

जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाने की परंपरा का उदाहरण भी इसी संदर्भ में सामने आता है। आज जन्मदिन के अवसर पर केक काटना और मोमबत्तियां बुझाना व्यापक रूप से प्रचलित है। दूसरी ओर, भारतीय धार्मिक परंपरा में दीपक को शुभता और प्रकाश का प्रतीक मानने वाले लोग इसे अलग दृष्टि से देखते हैं। दोनों परंपराओं के सांस्कृतिक संदर्भ अलग हैं। इसलिए किसी एक को अपनाने या दूसरे से दूरी रखने को अपने आप में किसी व्यक्ति की देशभक्ति या संस्कृति के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर भी एक विचारणीय प्रश्न अवश्य है—क्या हम अपनी संस्कृति से जुड़े प्रतीकों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं, जितनी संवेदनशीलता हम दूसरे सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए अपेक्षित करते हैं? यदि कोई व्यक्ति दीपावली पर दीप नहीं जलाना चाहता, उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति पूरे श्रद्धाभाव से दीप जलाता है, तो उसकी आस्था का उपहास क्यों किया जाए? इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दीप जलाकर सहभागिता करता है, तो उसकी आलोचना कार्यक्रम के राजनीतिक पक्ष पर होनी चाहिए, उसकी धार्मिक आस्था पर नहीं।

राजनीतिक बहस में पूर्व प्रधानमंत्रियों या दूसरे नेताओं के जन्मदिन समारोहों और कथित सरकारी खर्चों के उदाहरण भी दिए जाते हैं। ऐसे आरोपों को प्रमाणित करने के लिए संबंधित वर्ष, खर्च और आधिकारिक दस्तावेज सामने रखना आवश्यक है। बिना प्रमाण किसी व्यक्ति या पूर्व सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाना उचित नहीं है। आज की राजनीतिक बहस को मजबूत करने के लिए तथ्य चाहिए, केवल पुराने आरोप नहीं।

वास्तविक प्रश्न कुछ रुपये के तेल और बाती का नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि सार्वजनिक जीवन में हमारी प्राथमिकताएं क्या हों और हमारी भाषा कैसी हो। क्या राजनीतिक मतभेद इतने तीखे हो जाएँ कि सांस्कृतिक प्रतीक भी निशाने पर आ जाएँ? क्या धार्मिक आस्था को राजनीतिक समर्थन का पर्याय मान लेना सही है? क्या दीप जलाने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से किसी राजनीतिक विचार का समर्थक है? और क्या दीप न जलाने वाला व्यक्ति स्वतः संस्कृति-विरोधी है? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि व्यक्ति की आस्था और राजनीतिक पसंद को अलग-अलग समझना होगा।

दीपक किसी के लिए पूजा है, किसी के लिए परंपरा, किसी के लिए संस्कृति और किसी के लिए केवल प्रकाश। उसकी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन उसका अपमान किए बिना असहमति व्यक्त करना संभव है। हमारी संस्कृति की शक्ति केवल इस बात में नहीं कि हम दीप जलाते हैं; उसकी शक्ति इस बात में भी है कि हम विविध विचारों के बीच संवाद बनाए रखते हैं। दीप की लौ अंधकार को दूर करती है—उसी तरह विवेक, संयम और तथ्य सार्वजनिक बहस के अंधकार को दूर कर सकते हैं।

इसलिए दीप जलाइए या न जलाइए, यह आपका निर्णय है। किसी राजनीतिक आयोजन का समर्थन कीजिए या विरोध, यह भी आपका अधिकार है। लेकिन आस्था पर व्यंग्य करने से पहले और विरोध करते समय दूसरे की संवेदनाओं को चोट पहुँचाने से पहले इतना जरूर सोचिए—असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, पर सम्मान उसकी मयार्दा।

डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

चलते-चलते गलती से टकराने पर 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से किए कई वार

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी में नाबालिगों द्वारा हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब आनंद पर्वत इलाके में चलते समय गलती से टकराने पर आरोपितों ने एक 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। घायलावस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कुणाल ढींगरा के रूप में हुई है। आनंद पर्वत थाना पुलिस की टीम ने हत्या का मामला दर्ज सात घंटे के भीतर दो किशोरों समेत तीन आरोपितों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान आनंद पर्वत के तुषार के रूप में हुई है।

टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं संग हो रहा बड़ा भेदभाव

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) में अधिकारियों की भर्ती के दौरान पुरुषों की तुलना में महिला उम्मीदवारों के लिए बेहद कम पद निर्धारित किए जाने के आरोप पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस बारे में उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2022 से 2026 तक हर भर्ती प्रक्रिया में पुरुषों के लिए 12 से 18 पद रखे गए, जबकि महिलाओं के लिए केवल एक पद निर्धारित किया गया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका कुश कालरा ने दाखिल की है। इसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पदों के इस अंतर को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी में अब तक कितने लोग हो चुके शामिल, सौरभ दास ने दिया जवाब

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपने गठन के कुछ महीनों के भीतर ही देशभर में ना सिर्फ अपनी पहचान बना ली है, बल्कि प्रभाव जमाने की कोशिश में भी जुटी है। अभी तक गैर राजनीतिक रहने और प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने की बात कहने वाली सीजेपी संगठन विस्तार भी कर रही है। इस बीच सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने इस सवाल का जवाब दिया है कि अभी तक कितने लोग उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को दिए एक इंटरव्यू में सौरभ दास ने कहा कि उन्हें सटीक आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और 20-25 लाख लोग सदस्यता ले चुके हैं।

दिल्ली के सभी पार्कों का होगा सेफ्टी ऑ-डिट, पिंक पुलिस होगी तैनात; एलजी के आदेश

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। कालकाजी के अष्ट कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस, एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली के सभी पार्कों का एक हफ्ते में सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पार्कों के आसपास 'पिंक पुलिस की तैनाती करने को कहा है। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में बताया कि एलजी तरनजीत सिंह संधू ने लोक निवास में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए के वाइस चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने निर्देश दिया कि एक हफ्ते के भीतर दिल्ली के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट पूरा किया जाना चाहिए।

पूर्वी दिल्ली में एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 2 फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट भी लगेगी

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे (एनएच-709बी) पर पैदल यात्रियों की आवाजाही को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए दो नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को दोनों एफओबी के निर्माण की आधारशिला रखी। दोनों पुलों पर लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन दो फुट ओवर ब्रिज के अलावा भजनपुरा और गढ़ी मेंडू के पास एक और फुट ओवर ब्रिज को मंजूरी दी गई है। ये दोनों फुट ओवर ब्रिज गीता कॉलोनी/गांधी नगर और रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर में बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है।

व्हीआईपी को 4 घंटे में राहत, आम आदमी काट रहा चक्कर

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया पर भड़की कांग्रेस; डेट बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली कांग्रेस ने SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि रक्फ़प्रक्रिया में गरीब और अमीर यानी श्क्द्ध और आम आदमी के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है।

देवेंद्र यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस जारी हुआ तो महज चार घंटे में सभी कमियां दूर कर दी गईं, जबकि आम आदमी अपने नोटिस की खामियां दूर कराने के लिए शिविरों के चक्कर काट रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी मतदाताओं के नोटिस की कमियां प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाएं। यादव ने उन गरीब लोगों के वोट भी वापस जोड़ने की मांग की, जिनके घर बुलडोजर चलाकर ढहा दिए गए हैं।

सीएम के नोटिस पर उठाया सवाल

2002 की सूची में लिंक ढूंढना मुश्किल

दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मतदाता सूची में नाम न होना वजूद बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि 2002 की SIR सूची में लिंक ढूंढना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्फ़के तहत संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज भी आम आदमी की पहुंच में होने चाहिए। उनके मुताबिक, SIR की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों के घेरे में है।

सभी मतदाताओं की कमियां दूर हों

काजी निजामुद्दीन ने कहा कि केवल VIP मतदाताओं ही नहीं, बल्कि सभी मतदाताओं के नोटिस में मौजूद खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने दावे और आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग दोहराई।

कोर्ट कमिश्नर पर कुत्ता छोड़ने पर हाई कोर्ट सख्त, दो आरोपियों से 4 सप्ताह में मांगा हलफनामा

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। एक संपत्ति के विवाद में अदालत द्वारा नियुक्त किए गए लोकल कमिश्नर व अन्य पर निरीक्षण के दौरान कुत्ता छोड़ने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दो लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने प्रवेश लाखरा व चंदन शुक्ला के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जवाब में बताएं कि न्यायिक आदेशों का उल्लंघन और जानबूझकर कोर्ट कमिश्नर की अनदेखी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

मुख्मयंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी योजनाओं का संदेश देने वाली रैप्ड मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झड़ी

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत आईटीओ मेट्रो स्टेशन से सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी पहलों के संदेश वाली विशेष रैप्ड मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

मुख्मयंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहितकारी पहलों की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि पात्र लोग इनका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच मेट्रो ट्रेनों के 36 कोचों को दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित संदेशों से सजाया गया है। ये ट्रेनें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट लाइनों पर संचालित होंगी और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के लगभग 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करेंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक दिल्लीवासी इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

दिल्ली में नियम तोड़ने में कार चालक सबसे आगे, कटे 17.56 लाख रुपये का चालान

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में कार चालक सबसे आगे हैं। यातायात पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष 20 सितंबर तक कैमरों के माध्यम से कार चालकों के 17,56,160 चालान जारी किए गए हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर दोपहिया वाहन चालक रहे, जिनके 12,42,653 चालान कैमरों के जरिये काटे गए। इससे पता चलता है कि यातायात नियमों की निगरानी में कैमरा आधारित प्रवर्तन की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष 20 सितंबर तक राजधानी में कैमरों के माध्यम से विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 38,95,591 चालान जारी किए गए। पिछले वर्ष इसी अवधि में कैमरों के जरिये 37,34,673 चालान किए गए थे। इस तरह एक वर्ष में कैमरा चालान की संख्या में 1,60,918 की बढ़ोतरी हुई है यातायात पुलिस राजधानी की सड़कों पर नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए आइटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम), एएनपीआर (आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन), एआई आधारित स्मार्ट कैमरों और ओवार स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) व रेड लाइट वालेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) कैमरों के जरिए चालान जारी करती है।

अचानक हुआ फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। रघुवरपुरा इलाके में बुधवार दोपहर फ्रीज के कंप्रेसर में धमाका होने से आग लग गई। धमाके के बाद आग घर में आग लग गई। परिवार के तीन सदस्यों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग से घर में मौजूद पालतू कुत्ते की मौत हो गई। गांधी नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 3:36 बजे गली नंबर-2, दुर्गा मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया।

> परिवार बचा पर पालतू कुत्ते की मौत

अचानक हुआ धमाका फिर...

करीब 4:30 बजे दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लेने की सूचना दी। जांच में पता चला कि फ्रीज के कंप्रेसर में अचानक धमाका हुआ था। इसके बाद निकली चिंगारी से आसपास रखा घरेलू सामान आग की चपेट में आ गया। हादसे के समय घर में मौजूद तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। धमाके और आग की चपेट में आने से पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एडीएजी के पूर्व एमडी अमिताभ झुनझुनवाला को मेडिकल आधार पर मिली जमानत

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए गए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी।

बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला को राहत देते हुए न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि 70 साल के आरोपित अमिताभ को लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है और इसलिए पीएमएलए के तहत चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर पेश किए तथ्यों से पता चलता है कि आरोपित याची रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या, आस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ईडी ने अमिताभ झुनझुनवाला को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था कि अमिताभ की मेडिकल स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और सरकारी अस्पतालों द्वारा सुझाए गए टेस्ट और इलाज कस्टडी में मौजूद मेडिकल व्यवस्था के जरिए उपलब्ध हैं।

एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश

हालांकि, पीठ ने उक्त तर्कों को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि मेडिकल अपवाद का मकसद तब तक इंतजार करना नहीं है जब तक कि अपर्याप्त इलाज के नतीजे अपूरणीय न हो जाएं, बल्कि सही मामलों में दखल की अनुमति देना है। इसके साथ ही अदालत ने अमिताभ को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने अमिताभ को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगें और सुबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगें।

लेडी श्रीराम कॉलेज में ऑफलाइन क्लास बंद करना गलत फैसला : संदीप दीक्षित

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज की ओर से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित ऑफलाइन कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में किए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आना गंभीर चिंता का विषय है और कॉलेज को ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन करने की स्थिति बनना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में हुई रेप की घटना बेहद चिंताजनक है। पिछले कुछ समय से महिलाओं के खिलाफ गंभीर और घिनौने अपराध लगातार हो रहे हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लेडी श्रीराम कॉलेज जैसे संस्थान को सुरक्षा कारणों से ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन करना पड़ा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पढ़ने वाली छात्राओं, विशेषकर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच कितना भय होगा। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर यह गंभीर प्रश्न है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉलेज जैसे संस्थान में आने-जाने वाले लोगों को न्यूनतम सुरक्षा का एहसास भी नहीं कराया जा सकता तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठता है। उन्होंने इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के लिए गंभीर सवाल बताया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर दिल्ली के समाज की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इतने गंभीर अपराधों के बावजूद समाज में उस स्तर का आंदोलन या विरोध दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा पहले देखने को मिलता था। दीक्षित ने कहा कि ऐसे मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर समाज, महिलाओं और अपराध के विषय के तौर पर देखा जाना चाहिए। यदि सरकार पर इस तरह के मामलों का असर नहीं हो रहा है तो नागरिकों और जनता को अपनी आवाज उठाकर सरकार तक बात पहुंचानी होगी। एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति के दावों पर जारी घमासान के बारे में संदीप दीक्षित ने कहा कि सामने आई खबरें बेहद गंभीर हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रकाशित रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर इन बातों की पुष्टि हुई है। दीक्षित ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि रिपोर्ट सही है तो इससे चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं और फॉर्म में बदलाव किए गए और संसद के अधिकारों को भी नजरअंदाज किया गया।

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने उत्तरी क्षेत्र में स्थित बालक राम अस्पताल का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बुधवार को उत्तरी क्षेत्र में स्थित बालक राम अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने अस्पताल में प्रदान की जाने वाले सुविधाओं का जायजा लिया तथा नागरिकों की सुविधा के लिए सभी कर्मचारियों को पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने के आदेश दिए। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बालक राम अस्पताल के निरीक्षण के दौरान नागरिकों के सुचारू आवागमन के लिए मुख्य एप्रोच सड़क से अस्पताल के प्रवेश द्वार तक मार्ग को बनवाने के निर्देश दिए।

शालीमार बाग में मस्जिद पर कानून के तहत कार्रवाई, इसे राजनीतिक रंग देना गलतः प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। शालीमार बाग में अवैध मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम के विरोध पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है तो संबंधित धार्मिक समिति से भी सलाह ली गई होगी।

खंडेलवाल ने कहा, ह्लजो कुछ भी हुआ है, वह निश्चित रूप से परिस्थितियों के अनुसार किया गया है। अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस मामले को राजनीतिक रंग देना सही है। जमुई मामले में एनकाउंटर के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जाति और धर्म देखकर बयानबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगाता है। हमारी बिहार सरकार ने तुरंत पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की है। अब अगर सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करती है तो भी विपक्ष को एतराज है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भी विपक्ष को एतराज है। पहले विपक्ष को तय करना चाहिए कि उसे करना क्या है।

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स बनाने के उपराज्यपाल के निर्देश पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वह दिल्ली के एलजी के इस आदेश का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से हमारी पूरी पुलिस फोर्स सक्रिय रहती है, लेकिन महिलाओं से जुड़े मामलों में अगर हम पिंक फोर्स को और मजबूत करते हैं तो महिलाएं और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिसंबर 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया था और आज भारत नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है।

उन्होंने कहा, उसी तरह देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प भी पूरा किया जाएगा। नशे के खिलाफ जो संघर्ष करना होगा, वह किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि देश से नशे को खत्म किया जाएगा।

दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप के बाद एलएसआर कॉलेज ने की ऑनलाइन क्लास

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में एक नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन (एलएसआर) द्वारा क्लास ऑनलाइन करने के फैसले पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कदम राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश देता है।

दत्त ने कहा, जब एलएसआर कॉलेज महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए क्लास ऑनलाइन करता है, तो इससे साफ संदेश जाता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यह बात तब कही गई जब लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन ने पास के एक पार्क में 17 साल की लड़की के साथ कथित रेप के बाद मंगलवार को रेगुलर क्लास रद्द कर दीं और बुधवार के लिए उन्हें ऑनलाइन मोड में कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

> कांग्रेस बोली- राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं

दत्त ने कहा, देश के लिए एक बड़ा संदेश है। एलएसआर कॉलेज दुनिया के टॉप कॉलेजों में से एक है और इसके पूर्व छात्र पूरे देश में फैले हुए हैं। जब एसएसआर कॉलेज महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए क्लास ऑनलाइन करता है, तो इससे साफ संदेश जाता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, दुख की बात है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वालों ने पुलिस अधिकारी होने का नाटक किया। जिस तरह जंतर-मंतर पर कई प्राइवेट लोगों को पुलिस की लाठियां लिए देखा गया, उससे पता चलता है कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस के ज्यादातर अधिकारी वीआईपी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जबकि आम लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

दिल्ली में महिला सुरक्षा में बड़ी पहलः सड़कों पर उतरेंगी महिला पुलिसकर्मी, थमेगी अपराधों की रफ्तार

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। महिलाओं से संबंधित अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में एलजी के साथ कई मसले पर चर्चा के बाद पुलिस आयुक्त ने सभी 15 जिले के डीसीपी को अपने-अपने जिले के पार्कों, मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों और उन सभी जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों से गश्त कराने के निर्देश दिए जहां महिलाओं की आवाजाही अधिक होती है।

इसके बाद शाम करीब आठ बजे आयुक्त ने कालकाजी स्थित घटनास्थल (डीडीए पार्क) का दौरा किया जहां पुलिसकर्मी बनकर तीन युवकों ने किशोरी को हवस का शिकार बनाया। तमाम परिस्थितियों को जानने के बाद आयुक्त ने बुधवार को मुख्यालय में दोनों जोन के विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था देवेश चंद्र श्रीवास्तव व नीरज ठाकुर सहित महिला एवं बाल सुरक्षा के विशेष आयुक्त विवेक किशोर के साथ महिला सुरक्षा के मसले पर घंटों चर्चा की और अहम फैसले लिए।

अधिकारियों के कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में महिलाकर्मी ड्यूटी

इस दौरान आयुक्त ने सुझाव दिया कि मुख्यालय में तमाम अधिकारियों के कार्यालयों में ड्यूटी करने वाली महिला कर्मियों का इस्तेमाल फील्ड ड्यूटी में किया जाए। थानों, यूनिटों, रेंज व जिले में बैठने वाले अधिकारियों के कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में महिलाकर्मी ड्यूटी करती हैं, थानों में ड्यूटी आफिसर भी महिलाकर्मी होती हैं जिन्हें कम किया जा सकता है।

आयुक्त का मानना है कि जब पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या कम है तो ऐसी परिस्थिति में कार्यालयों में ड्यूटी करने वाली महिला कर्मियों से सड़कों, बाजारों, स्कूल-कालेजों व महिला अपराध के संभावित इलाकों में गश्त कराई जाए। महिला कर्मियों की सड़कों पर मुस्तैदी बढ़ने पर महिलाओं से संबंधित अपराध पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। पीड़ित महिलाएं तुरंत महिला पुलिस से अपनी शिकायतें कर सकेंगी।

एक-एक महिला थाना खोलने के लिए जगह का चयन करने के निर्देश

अबतक केवल उत्तरी जिले में एक महिला थाना है। आयुक्त ने अधिकारियों से फिलहाल सभी छह रेंज में एक-एक महिला थाना खोलने के लिए जगह का चयन करने के निर्देश दिए। अभी कुछ जिलों में 15 महिला पीसीआर चल रही हैं। इसकी भी संख्या बढ़ाकर हर जिले में करने के निर्देश दिए गए। स्कूटी से महिला कर्मियों द्वारा गश्त करने की सुविधा भी चंद जिले में ही है इसको लेकर भी सभी जिले में यह सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। मंगलवार को घटनास्थल का दौरा करने के दौरान आयुक्त ने पाया कि वारदात स्थल के आसपास अंधेरा था, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस तरह की खामियां के बाद आयुक्त ने बुधवार को कई दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें डार्क स्पॉट, खराब पड़े स्ट्रीट लाइटें और पार्कों के आसपास बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे की पहचान करने, पार्कों की टूटी दीवारों, गेटों के बारे में सिविक एजेंसियों को सूचित करने, बीट स्टाफ और सुरक्षा गार्डों की पार्कों में तैनाती जेबकतरों व अपराधियों के पार्कों में प्रवेश पर पाबंदी और पार्कों में फिर से साइकिल गश्त शुरू करने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त वार्ता

उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर गरजी भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा

मुरादाबाद, वेब वार्ता

भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा ने अलीगढ़ और मुरादाबाद आदि जनपदों में वाल्मीकि समाज के उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को रोकने एवं वाल्मीकि समाज की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को पदाधिकारी संगठन के बैनर के साथ कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार वाल्मीकि समाज पर जारी उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में विफल है कहा गया कि अलीगढ़ में सचिन राघव द्वारा वाल्मीकि समाज के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आरोप लगाया गया है कि सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है इसके अलावा हाथरस में मनीष वाल्मीकि के कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं ग्राम हरियाणा में दबंगों द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया गया जिसमें संबंधित धाराओं में सुबोध विजेंद्र गौरव विनोद अरविंद अर्जुन बॉबी आदि निवासी हरियाणा थाना कुंदरकी मुरादाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने व वाल्मीकि समाज की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग उठाई गई है।

कानपुर में देशभर के ईएनटी विशेषज्ञों का होने जा रहा समागम

वेब वार्ता, कानपुर

डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज एवं एआईओ कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में 43वां यूपीएओआईकॉन - 2026 आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन 24 से 27 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जायेगा। इस चार दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन ईएनटी एवं हेड-नेक सर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों, आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा व्यावहारिक शल्य-कौशल के आदान-प्रदान करने का महत्वपूर्ण मंच होगा।

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के सभागर में प्रेसवार्ता के दौरान एआईओ कानपुर के चेयरमैन एवं ईएनटी के विभागध्यक्ष डॉ हरेंद्र कुमार ने बताया कि सम्मेलन के प्रथम दो दिन, 24 एवं 25 सितंबर, प्री-कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होगी। इसमें कैडेवरिक हैंड्स-ऑन डिसेक्शन वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रात :काल कान से संबंधित, टेम्पोरल बोन डिसेक्शन तथा सायंकाल में नाक से संबंधित, एफईईएस का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पंजीकृत प्रतिभागियों को कैडेवर पर प्रत्यक्ष रूप से शल्य-कौशल का अभ्यास कराना है, ताकि वे इन तकनीकों को वास्तविक मरीजों के उपचार में सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। वही 25 सितंबर को लाइव सर्जिकल वेबकास्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण जयपुर से होगा।

व्यवस्थाओं के साथ आस्था का संगम, नंगे पांव श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे डीएम-एसपी

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। बुंदेलखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान से जुड़े ऐतिहासिक जल विहार महोत्सव में इस बार प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ अधिकारियों की आस्था में सहभागिता भी देखने को मिली।

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक संजीव बाजपेई ने आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी के साथ श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर पूजा-अर्चना की और महाआरती में शामिल हुए।

महोत्सव के दौरान दोनों अधिकारी नंगे पांव श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे और डोलों में विराजमान भगवान के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद महाआरती में भी सहभागिता की। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जिले की सुख-शांति, समृद्धि और निरंतर विकास की कामना की।

जल विहार महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। सुम्मेरा तालाब सहित प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। पार्किंग, प्रकाश, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं की अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे आयोजन के दौरान मुस्तैद रहीं, जिससे भीड़ के बीच व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहीं और महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

देवरिया में कांग्रेस के तत्वाधान में 2 अक्टूबर को होगी महात्मा गांधी क्विज प्रतियोगिता

वेब वार्ता, देवरिया

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के तत्वावधान में देशभर में महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में देवरिया में भी दो अक्टूबर को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय संयोजक मानवेन्द्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि देवरिया में यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दिव्य शक्ति मैरिज लॉन, चीनी मिल रोड पर आयोजित होगी। इसमें 15 से 22 वर्ष की आयु के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रतिभागियों का पंजीकरण ऑनलाइन क्यूआर कोड तथा ऑफलाइन फार्म के माध्यम से कराया जाएगा।

नवागत जिलाधिकारी अनुनय झा ने संभाला कार्यभार

मुरादाबाद (वेब वार्ता)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किए जाने के क्रम में हरदोई से स्थानांतरित होकर आए अनुनय झा ने मुरादाबाद में बुधवार को जिलाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वर्ष 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अनुनय झा का जिलाधिकारी के रूप में मुरादाबाद तीसरा जनपद है इससे पूर्व महाराजगंज एवं हरदोई में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं

मूल रूप से बिहार प्रांत में जन्मे जिलाधिकारी अनुनय झा का प्रशासनिक सफर उत्तर प्रदेश के जनपद की ऐतिहासिक एवं धार्मिक बृज भूमि मथुरा से शुरू हुआ है नवागत जिलाधिकारी अनुनय झा के प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो पता चलता है कि वह एक अनुभवी अधिकारी है मथुरा वृंदावन नगर निगम में नगर आयुक्त झांसी में एसडीएम अलीगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी के बाद महाराजगंज के जिलाधिकारी बने तदोपरांत हरदोई के जिलाधिकारी बनाए गए। उत्तर प्रदेश की आईएएस ग्रेडेशन सूची में उनका नाम 2015 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में दर्ज है।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आलोचना तत्वों के आधार पर होनी चाहिए व्यक्तिगत नहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी समाचार को प्रसारित व प्रकाशित करने से पूर्व प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि अवश्य कर ली जाए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताए रहेंगी उन्होंने कहा कि हर जनपद की अपनी अलग समस्याएं व भौगोलिक जनक परिस्थितियां और समस्याएं होती हैं जिनको समझने के बाद ही जनहित में निर्णय लिए जाएंगे

मीडिया एवं आमजन से सहयोग की अपील भी की है इससे पूर्व कलेक्ट्रेट पहुंचने पर नवागत जिलाधिकारी अनुनय झा का उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया और अपना परिचय भी कराया। इस दौरान एडीएम फाइनेंस ममता मालवीय एडीएम प्रशासन संगीता गौतम एडीएम सिटी अंकुर श्रीवास्तव सहित अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय और सभी उप जिलाधिकारी एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे।

जनता की छोटी समस्या पर भी डीएम की बड़ी तत्परता

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की गंभीरता उस समय देखने को मिली, जब एक ग्रामीण अपने घर के पास खराब पड़े हैंडपंप की शिकायत लेकर दूसरी बार उनके पास पहुंचा। शिकायत सुनते ही जिलाधिकारी ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को फोन पर कड़ी नाराजगी जताई और शाम तक हैंडपंप दुरुस्त कराकर पेयजल की समस्या दूर करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके घर के पास लगा हैंडपंप काफी समय से खराब है। हैंडपंप से पानी नहीं निकलने के कारण परिवार को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या के समाधान के लिए वह पहले भी शिकायत कर चुका था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी समस्या को लेकर वह दोबारा जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित जिम्मेदारों से फोन पर बात की और शिकायत के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिलाधिकारी ने जिले के अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। केवल शिकायत दर्ज कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

डीजे पर रोक को लेकर सामाजिक-धार्मिक संगठनों ने डीएम-एसपी को सौंपा पत्र

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। नगर क्षेत्र में शोभायात्राओं एवं जुलूसों के सुचारु,सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह ह्यधीरूह्ण के नेतृत्व में आयोजित सर्वसमाज की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन हेतु विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया है।

पत्र में कहा गया है कि नगर क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक अनुयायियों एवं संगठनों से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों तथा जनहित,सुरक्षा एवं नगर की शांति-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हिंदू,मुस्लिम,सिख सहित विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं एवं प्रतिष्ठित नागरिकों की बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संगठनों ने इन निर्णयों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिला प्रशासन से शीघ्र विस्तृत प्रशासनिक मार्गदर्शिका जारी करने का अनुरोध किया है।

डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग

सर्वसमाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि बलरामपुर नगर में किसी भी शोभायात्रा अथवा जुलूस के दौरान डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में डीजे वाहनों के प्रवेश पर भी प्रभावी रोक लगाने तथा डीजे संचालकों की प्रशासन के स्तर पर बैठक कर उन्हें पूर्व में ही प्रतिबंध की जानकारी देकर अनुपालन के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है।

पत्र में शोभायात्रा अथवा जुलूस में वाहन सहित स्थापित मूर्ति की कुल ऊंचाई अधिकतम 12 फीट निर्धारित करने की मांग की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। विद्युत तारों को व्यवस्थित करने की मांग

शोभायात्राओं एवं जुलूसों के निर्धारित मार्ग पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही आयोजन से पूर्व विद्युत विभाग द्वारा मार्ग में लटक रहे तारों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित कर 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने की मांग की गई है,ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने का भी अनुरोध किया गया है।

डीजे वाहनों के नगर में प्रवेश को रोकने के लिए प्रमुख प्रवेश मार्गों पर प्रभावी निगरानी एवं आवश्यक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान मेला आयोजित

वेब वार्ता, देवरिया/। देवरिया जिले में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत मंगलवार को देवरिया कृषक प्रशिक्षण केंद्र, बैतालपुर में जनपद स्तरीय कृषि गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार ने किसानों को मक्का की खेती के प्रति जागरूक करते हुए इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

कृषि गोष्ठी एवं किसान मेले में कृषि विज्ञान केंद्र, मल्हना भाटपार रानी के प्रभारी डॉ. मान्धाता सिंह एवं डॉ. अंकुर ने किसानों को मक्का की उन्नत खेती तथा प्राकृतिक खेती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर मक्का की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी किसानों को दी। उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ-साथ मिलेट्स (श्रीअन्न), दलहनी एवं तिलहनी फसलों तथा मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी उदयशंकर सिंह, सदर क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि नवीन सिंह, पशुपालन विभाग से जीतन यादव, विषय वस्तु विशेषज्ञ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सलाहकार दिग्विजय नाथ सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

आधुनिक तकनीक से सटीक जांच, अनावश्यक सर्जरी से बचेंगे मरीज

प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच का अंतर बताएगी नई पैथोलॉजिकल तकनीक

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और एलएलआर चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग ने प्रोस्टेट कैंसर के सटीक और त्वरित निदान की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) संजय काला के मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं ने आधुनिक बायोमार्कर तकनीक का सफल मूल्यांकन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलते हुए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक मेडिसिन एंड फामेर्सी (जेएएमपी) में प्रकाशित किया गया है। यह महत्वपूर्ण शोध मुख्य शोधकर्ता डॉ. अनिरुद्ध जैन, डॉ. नीलिमा वर्मा और विभागाध्यक्ष डॉ. लुबना खान की देखरेख में पूरा किया गया।

शोधकताओं ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। हालांकि, शुरूआती स्टेज के प्रोस्टेट कैंसर और सामान्य प्रोस्टेट वृद्धि (बीपीएच) के लक्षणों में काफी समानता होती है। बायोप्सी के छोटे सैंपलों में इन दोनों के बीच फर्क स्पष्ट कर पाना डॉक्टरों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा है। हांलकि इस समस्या के समाधान के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 91 प्रोस्टेट बायोप्सी सैंपलों का गहन अध्ययन किया गया। इसमें पी63 और एचएमडब्लूसीके जैसे आधुनिक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री (आईएचसी) बायोमार्कर्स का मूल्यांकन किया गया।

शोधकताओं के अनुसार, इस आधुनिक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस से मरीजों को दोहरे स्तर पर राहत मिलेगी। सामान्य वृद्धि (बीपीएच) के जिन मरीजों को कैंसर नहीं है, वे अनावश्यक जटिल और जोखिम भरे ऑपरेशनों से बच सकेंगे। गंभीर कैंसर पीड़ित मरीजों में बीमारी की पहचान शुरूआती चरण में ही हो जाएगी, जिससे उन्हें बिना समय गंवाए तत्काल जीवनरक्षक इलाज मिल सकेगा। पैथोलॉजी विभाग का यह शोध सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर डायग्नोसिस को अधिक सुलभ और सटीक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बारिश थमी, फिर भी कंदवा की कॉलोनियों में भरा सीवर का गंदा पानी

वाराणसी, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। बारिश थमे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कंदवा वार्ड की कई कॉलोनियों और गलियों में जलभराव की समस्या अब भी बनी हुई है। शिवाजी नगर कॉलोनी से लेकर सुरभी नगर तक सड़कों पर सीवर का गंदा पानी जमा होने से स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित है। कर्मदेश्वरपुरम नगर कॉलोनी, राजीव नगर कॉलोनी और पाल बस्ती सहित कई इलाकों में लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलनिकासी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

नवागत डीएम का कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों पर औचक निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नवागत जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयीन कार्यों की प्रगति, लंबित पत्रावलियों तथा अभिलेखों की स्थिति की जानकारी ली और कार्यों में समयबद्धता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय, नजारत अनुभाग, संग्रह अनुभाग, भूलेख अनुभाग, जिला निर्वाचन कार्यालय, अभिलेखागार, जनसुनवाई/आईजीआरएस कार्यालय, शस्त्र अनुभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय सहित अन्य पटलों एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं पटल सहायकों से उनके पटल पर किए जा रहे कार्यों तथा लंबित पत्रावलियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित पत्रावलियों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी अभिलेखों और पत्रावलियों को व्यवस्थित ढंग से रखने के साथ उनकी सुरक्षित रख-रखाव व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा।

डीएम ने सभी पटलों पर पटल सहायक के नाम एवं पदनाम की पट्टिका अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को संबंधित कर्मचारी की आसानी से पहचान हो सके। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर और सभी कार्यालयों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय में आने वाले फरियादियों एवं आमजन के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो।

ओम प्रकाश राजभर का दिमाग खिसक गया है, अच्छे चिकित्सक से उपचार कराएं: शिवपाल यादव

वेब वार्ता, देवरिया

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि राजभर का दिमाग खिसक गया है और उन्हें अब एक अच्छे चिकित्सक से अपना उपचार कराना चाहिए।

श्री यादव आज देवरिया जिले के बरहज स्थित बीआरडीबीडी पीजी कॉलेज परिसर में पूर्व सांसद, प्रखर समाजवादी चिंतक और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे स्व. मोहन सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा ओमप्रकाश राजभर के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जायेगा और पूर्वांचल एक अलग राज्य बनेगा। पूर्वांचल राज्य बनने पर राजभर समाज का बेटा वहां का पहला मुख्यमंत्री होगा।

इस सवाल पर श्री यादव ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनका दिमाग खिसक गया है। उन्हें एक अच्छे चिकित्सक की जरूरत है। अगर उन्हें कोई अच्छा चिकित्सक नहीं मिल रहा है तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं।हम उन्हें अच्छे चिकित्सक का पता बता देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहने के बाद ओमप्रकाश राजभर बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। जनता सब समझती है।

हरदोई में नवागत डीएम राहुल पाण्डेय ने पहले दिन की जनसुनवाई

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नवागत जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट में पहली जनसुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जनसुनवाई में कुल 64 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का नियमानुसार, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को अपनी समस्या के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीएम राहुल पाण्डेय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को राहत दिलाने का प्रयास किया जाए।

ओएनजीसी ने समुद्र में खोजा गैस का कुंआ, कोणार्क तट से 43 किलोमीटर है दूर

गैस को पाइपलाइन और ऑनशोर प्रोसेसिंग प्लांट तक लाना होगा आसान, खर्च भी कम आएगा

नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 18 सितंबर को समंदर में गैस का बड़ा भंडार ढूंढ़ निकाला है। ओएनजीसी ने एमएन-डीडब्ल्यू18-1-एच-टी कुएं की खोज ओडिशा के कोणार्क तट से करीब 43 किलोमीटर दूर 1,441 मीटर से 1,452 मीटर की गहराई में की है। ओएनजीसी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उसने एक कुएं में यह खोज की है। इस कुएं की खुदाई 1,623 मीटर की तय गहराई तक की गई थी। यह राष्ट्रीय अपतटीय खोज मिशन के तहत महानदी बेसिन में मिली पहली बड़ी सफलता है, जो यह साबित करता है कि भारत के पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में अभी भी ऊर्जा के ऐसे विशाल भंडार मौजूद हैं, जिनकी खोज अभी तक नहीं की जा सकी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी ने बताया कि कुएं की खुदाई के वक्त 1,441 मीटर और

1,452 मीटर की गहराई के बीच गैस मिली है। कुआं कोणार्क के तट से करीब 43 किमी दूर स्थित है। अगर आगे की जांच और मूल्यांकन में यह खोज व्यावसायिक रूप से फायदेमंद साबित होती है, तो इस स्थिति से जल्द कमाई शुरू करने में मदद मिल सकती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कुआं तट के करीब है इसलिए गैस को पाइपलाइन और ऑनशोर प्रोसेसिंग प्लांट तक लाना आसान होगा और इसमें खर्च भी कम आएगा।

ओएनजीसी ने कहा कि इस कुएं से अच्छे फ्लो और रिजर्वायर प्रेशर के साथ गैस निकल रही है। इस इलाके में हुई दूसरी खोजों के साथ-साथ यह खोज भी पीएनजी रूल्स, 2025 के तहत साझा सुविधाओं के जरिए विकास के लिए एक विकल्प हो सकती है, जिससे डीपवॉटर रिसोर्स का उत्पादन शुरू हो सकेगा। ओएनजीसी इन सभी अलग-अलग गैस के कुओं को एक ही नेटवर्क से जोड़कर उनका संचालन कर सकेगी। यह गैस की खोज ऐसे समय में हुई है जब सरकार घरेलू स्तर पर खोज और उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, खासकर ऑफशोर और डीपवॉटर इलाकों में। सरकार ने जुलाई में 84,000 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन पहल शुरू की थी ताकि ड्रिलिंग की लागत और खोज से जुड़े जोखिमों को कम करके भारत के ऑफशोर इलाकों में खोज को बढ़ावा दिया जा सके।

महत्वपूर्ण ख़बर

सऊदी ने खोल दिया दरवाजा, कुछ भी कर लें ईरान के गुर्गे, धकाधक होगी तेल की सप्लाई

- सऊदी अरब। मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति को लेकर बाजार में राहत के संकेत मिलने लगे हैं. सऊदी अरब ने मंगलवार को अपनी ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को दोबारा चालू कर दिया है. इसके साथ ही लाल सागर के किनारे स्थित यानबू बंदरगाह से भी कच्चे तेल का निर्यात फिर शुरू होने की संभावना है. इस खबर का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर तुरंत देखने को मिला और ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2 डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों के मुताबिक पाइपलाइन फिलहाल कम क्षमता पर चल रही है लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ेगी. सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको इसकी पंपिंग क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस पाइपलाइन की क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि मौजूदा स्थिति में इसे लगभग 40 लाख बैरल प्रतिदिन की दर तक लाने का लक्ष्य है.

जयपुर की वर्कशॉप में आग: आठ मर्सिडीज जलकर खाक

- जयपुर। जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र स्थित सीतापुरा के बालाजी मार्केट में मंगलवार रात मर्सिडीज कंपनी के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वर्कशॉप का बड़ा हिस्सा लपटों से घिर गया और करीब आठ कारें, एसेसरीज व महंगे वाहन पार्ट्स जलकर खाक हो गए।

सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा स्थित बालाजी मार्केट में मंगलवार रात मर्सिडीज कंपनी के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में वर्कशॉप का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिर गया। हादसे में वर्कशॉप में खड़ी करीब आठ कारें, एसेसरीज और महंगे वाहन पार्ट्स जलकर खाक हो गए।

अब गूगल सीधे भारत सरकार को देगा बाल यौन शोषण मामलों की सूचना

सीधे रिपोर्टिंग से खतरे में फंसे बच्चों तक पहुंचने और कार्रवाई करने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा और बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ लड़ाई दिग्गज टेक कंपनी गूगल अब भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की सूचना सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजने पर सहमत हो गई है।

अब तक ऐसी किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की सूचना पहले अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भेजी जाती थी, जिसके बाद वह जानकारी भारत पहुंचती थी। सीधे रिपोर्टिंग शुरू होने से भारतीय पुलिस और साइबर एजेंसियों को खतरे में फंसे बच्चों तक फौरी तौर पर पहुंचने और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने, उसे तुरंत हटाने और एजेंसियों को रिपोर्ट करने के लिए तकनीकी संसाधनों में लगातार बड़ा निवेश कर रही है। यह फैसला मेटा द्वारा पिछले सप्ताह लिए गए फैसले के ठीक बाद आया है। मेटा ने भी भारत सरकार के दबाव के बाद बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों का डेटा सीधे संबंधित भारतीय जांच एजेंसियों से साझा करने की व्यवस्था लागू की थी।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत में काम कर रही सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों के लिए बच्चों की डिजिटल सुरक्षा एक गैर-परक्राम्य सिद्धांत है। अधिकारियों के मुताबिक सूचना आने में प्रक्रियागत देरी होती थी, जिससे उन मामलों में भारी नुकसान होता था जहां किसी बच्चे की जान या सुरक्षा पर तत्काल गंभीर खतरा मंडरा रहा होता था। वर्ष 2025 में एनसीएमईसी की साइबरटिपलाइन को दुनियाभर से बच्चों के संभावित यौन शोषण से जुड़ी 2.13 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं।

भारत में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाना, देखना, अपने पास रखना, शेयर करना, बेचना या प्रसारित करना पोक्सो एक्ट और आईटी कानून के तहत गैर-जमानती अपराध है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुमार्ना है। दोबारा अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और भारी जुमार्ना है। यदि इंटरनेट पर कहीं भी ऐसी सामग्री दिखाई दे, तो उसे किसी भी हाल में डाउनलोड, फॉरवर्ड या शेयर न करें। संबंधित प्लेटफॉर्म पर तत्काल फ्लैग करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल अथवा स्थानीय पुलिस/साइबर सेल में सूचना दर्ज कराएं।

जिनपिंग के अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप से होगा आमना-सामना

25 सितंबर को होगी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह अमेरिका के तीन दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि शी जिनपिंग तेईस से पच्चीस सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन के अनुसार, इस आगामी बैठक के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चीन-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास से जुड़े तमाम प्रमुख मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। चीन का यह भी कहना है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच रचनात्मक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने, आपसी संवाद को बढ़ाने और वर्तमान मतभेदों को उचित तरीके से प्रबंधित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दुनिया की इन दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच हो रही इस मुलाकात को व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक और भू-राजनीतिक तनावों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर एक विशेष पहल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड खुद बुधवार को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे, जबकि दोनों नेताओं के बीच मुख्य और निर्णायक बैठक गुरुवार को होने की उम्मीद है। पिछले साल मई में ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान बीजिंग पहुंचने पर चीनी उपराष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया था, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति का यह व्यक्तिगत स्वागत दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीतिक गर्माहट लाने का संकेत देता है। हाल ही में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि वे इस मुलाकात के दौरान व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से लेकर लगभग हर संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले लगभग एक साल से दोनों देशों के बीच टैरिफ और व्यापारिक मोर्चे पर केवल एक अस्थायी समझ ही बन पाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस या स्थायी व्यापार समझौता नहीं हो सका है, जिसे इस बैठक में अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा सकता है।

इमरान के बेटे ने लगाए गंभीर आरोप कहा-

रिश्तेदारों को गायब करा रहे मुनीर

इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके परिवार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान के छोटे बेटे कासिम ने पाकिस्तान के शक्तिशाली आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाया है। कासिम का कहना है कि मुनीर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी खुन्नस निकाल रहे हैं, और उन्हें डर है कि उनके पिता को जेल में धीरे-धीरे मौत की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान की सरकार घबरा गई है। कासिम ने कहा कि हमारे रिश्तेदारों को धीरे धीरे गायब कराने का काम आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर करा रहे हैं।

कासिम ने अपने एक बयान में बताया कि इमरान की तीन बहनों- अलीमा खान, उज्मा खान और नूरीन नियाजी को भी उठा लिया गया है। ये लोग इमरान खान को रिहा करने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली थीं। उन्होंने कहा कि उनकी सभी बुआ और उनके परिवार को नकाबपोश बंदूकधारियों ने आधी रात को उनके घर से उठा लिया। उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है, और यह भी जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें कहां पर रखा गया है। परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कासिम ने आशंका जताई है कि बहुत जल्द उनके परिवार के साथ भी यही सुलूक हो सकता है। इमरान की तीनों बहनों के वकील का कहना है कि उन सभी पर सार्वजनिक रूप से अशांति फैलाने का आरोप है, जिसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है और 30 दिनों के लिए जेल में रखा गया है। कासिम ने इस हिरासत की निंदा करते हुए कहा कि अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों के घरों में जबरन प्रवेश किया और बिना किसी स्पष्टीकरण या गिरफ्तारी का कारण बताए उन्हें वाहनों में बैठा लिया। उन्होंने इस व्यवहार को आपराधिक और अक्षम्य बताया। यह भी सामने आया कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान की दोनों बहनों को उनके बच्चों और अलीमा खान के बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें बख्तरबंद वाहन में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। अधिकारियों की इस चिंता पर कि इमरान की बहनें अशांति फैला सकती थीं, कासिम ने कहा कि सरकार उनके पिता की लोकप्रियता से दहशत में है। उन्होंने बताया कि उनके फुफेरे भाई-बहन और बुआ लोग आमतौर पर खामोश ही रहते हैं, केवल अलीमा बुआ थोड़ी मुखर हैं।

यूएई में भारतीय की नृशंस हत्या, शव के 9 टुकड़े मिले

बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रकाश, बेहतर जिंदगी की तलाश में सालों पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह पहुंचे थे। उनकी सामान्य जिंदगी जुलाई में उस समय बिखर गई जब एक खबर ने उनके परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। प्रकाश की हत्या हो चुकी थी, और जो सामने आया वह और भी खौफनाक था, उनके शव के नौ टुकड़े कर दिए गए थे। इस मामले में एक बड़ा रहस्य यह भी है कि प्रकाश की पत्नी और बच्चा अब तक लापता हैं, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनके साथ कोई अनहोनी हुई है या पत्नी इस हत्याकांड में शामिल है।

आधी रात को हुए कमांडो एक्शन में ट्रिपल मर्डर का आरोपी ढेर

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंगलवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ एक शख्स ने घर में पूजा करा रही अपनी पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अरविंद सिंह अपने तीन बच्चों के साथ एक कमरे में छिप गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देर रात लखनऊ से एटीएस के कमांडो को बुलाया गया, जिन्होंने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए एक विशेष कमांडो कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने कमांडो पर भी गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में कमांडो टीम ने उसे ढेर कर दिया। बेहद दुखद बात यह है कि इस मुठभेड़ में आरोपी के चार साल के बेटे की भी मौत हो गई। जबकि बड़ी बेटी के हाथ में गोली लगी है। घटना के बाद बनारस से पहुंचे एडीजी ने बताया कि आरोपी ने कमांडो पर पांच राउंड फायरिंग की थी, जिसके जवाब में कमांडो टीम ने चार राउंड गोलियां चलाईं।

घटना शंभूपुर गांव की है, जहाँ ग्रामीणों के अनुसार अरविंद सिंह पर भूत प्रेत का साया होने का शक था। वह शराब का भी आदी था। अरविंद के ऊपर से कथित भूत प्रेत का साया हटाने के लिए उसके घर में चार दिन से एक अनुष्ठान चल रहा था, जिसकी पूणार्हुति बुधवार को होनी थी। मंगलवार शाम को अरविंद की पत्नी 32 वर्षीय बबिता अनुष्ठान के लिए पूजा पर बैठी थी। अहरौला इलाके के पठखौली गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र पाठक और छिताना गोझा गांव निवासी 50 वर्षीय अखिलेश मिश्र समेत चार पुजारी इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे थे।

बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे अरविंद नशे की हालत में घर पहुंचा और अनुष्ठान का विरोध करने लगा। इस दौरान उसने पुजारियों से आधार कार्ड मांगा, जिसे लेकर पुजारियों से उसकी बहस होने लगी। जब बबिता ने अरविंद को शांत करने की कोशिश की, तो वह और आक्रोशित हो गया और घर से अपनी रिवॉल्वर ले आया। उसने पहले अपनी पत्नी बबिता को गोली मारी, और फिर दोनों पुजारियों महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्र पर भी फायर झोंक दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय मौजूद दो अन्य पुजारी और परिजन डरकर घर से बाहर भाग गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोपी अरविंद अपने तीन बच्चों छह साल की बेटी, आठ माह की बेटी और चार साल के बेटे को ढाल बनाते हुए एक कमरे में जा छिपा। एडीजी ने घटना के बाद बताया कि आरोपी अरविंद मानसिक रूप से बीमार था।

सुलावेसी द्वीप में हजारों साल पहले भी सुपारी चबाते थे इंसान

सिडनी। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में मिले लगभग 25 हजार साल पुराने मानव दांतों की गहन जांच से यह संकेत मिला है कि उस समय के शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय भी सुपारी का इस्तेमाल करते थे। इस पुरातात्विक खोज ने इंसानों में नशीली या उत्तेजक चीजों के इस्तेमाल की शुरूआत को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की प्रचलित धारणा को नई चुनौती दी है। यह खोज इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे नशीले पौधे के इस्तेमाल का प्रमाण खेती-बाड़ी की शुरूआत होने से हजारों साल पहले का हो जाता है, जो मानव सभ्यता के विकास क्रम में एक नई रोशनी डालता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के शोधकताओं के अनुसार, सुलावेसी में मिले इन प्राचीन दांतों पर एक विशेष प्रकार की घिसावट और गोलाकार निशान पाए गए।

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान लंबे समय तक साबुत सुपारी को मुंह में रखने और चबाने से बने होंगे। दांतों की रासायनिक जांच में ह्यएरेकोलीनह्ल नामक रसायन के संकेत भी मिले, जो सुपारी में पाया जाने वाला एक प्रमुख सक्रिय तत्व है और इसके नशे या उत्तेजक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। अब तक आम धारणा यह रही है कि नशीले पेय या पौधों का इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती और स्थायी बस्तियों के विकास के बाद बढ़ा, जब लोगों ने फसलों की पैदावार और किण्वन प्रक्रियाओं को समझा।

प्राचीन साक्ष्यों में लगभग 13 हजार साल पहले जौ से तैयार किण्वित पेय (जैसे बीयर) के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है, जिसे प्रारंभिक नशीले पदार्थ के उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता था। यह नई खोज इससे कहीं अधिक पुरानी है और यह बताती है कि शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय भी पौधों के ऐसे गुणों से परिचित हो सकते थे, जो शरीर और दिमाग पर असर डालते हैं। यह ज्ञान उन्हें अपने परिवेश और वनस्पति की गहरी समझ से प्राप्त हुआ होगा। शोधकताओं ने इस परिकल्पना को और समझने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग भी किए कि बिना चूने के भी सुपारी का असर संभव था या नहीं, क्योंकि आधुनिक सुपारी के सेवन में अक्सर चूने का उपयोग किया जाता है। उन्होंने साबुत सुपारी को कृत्रिम लार में कई घंटों तक रखा और फिर तैयार द्रव की जांच की। प्रयोग में एरेकोलीन के ऐसे प्रभावों के संकेत मिले, जो शरीर के कुछ तंत्रिका रिसेप्टरों को प्रभावित कर सकते हैं।

इससे वैज्ञानिकों को प्राचीन दांतों पर मिले रासायनिक प्रमाण को समझने में मदद मिली और यह पुष्टि हुई कि सुपारी को चूने के बिना भी चबाने पर उसका प्रभाव संभव था। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि प्राचीन लोग सुपारी का इस्तेमाल केवल नशे के लिए ही नहीं, बल्कि दर्द कम करने के उद्देश्य से भी करते रहे होंगे। उस दौर में दांतों की समस्या और दर्द का इलाज करने के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, और सुपारी के कुछ दर्दनिवारक गुण माने जाते हैं। हालांकि, सुपारी के लगातार सेवन से दांतों पर अत्यधिक घिसावट होने की संभावना भी रहती है, जैसा कि इन प्राचीन दांतों में देखा गया। आज सुपारी का इस्तेमाल भारत सहित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई हिस्सों में पान और अन्य उत्पादों के रूप में व्यापक रूप से होता है।

पोखरण-2 के बाद भारत ने कैसे किया था अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना: 25 साल पुरानी कहानी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच फिर व्यापार और प्रतिबंधों को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 2026 के लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह कानून अमेरिकी प्रशासन को रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की ताकत देता है, हालांकि भारत पर ऐसा शुल्क अपने आप लागू नहीं होता। इसके बाद 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत-अमेरिका संबंधों का दौर फिर से चर्चा में आ गया है, जब वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और भारत ने उनका मजबूती से सामना किया था।

11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए। इसके मात्र दो दिन बाद, 13 मई को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ग्लेन संशोधन के तहत भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों में व्यापक विदेशी सहायता पर रोक, कुछ रक्षा नियातों पर प्रतिबंध और अन्य आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर रोक शामिल थी। अमेरिकी नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत पर परमाणु अप्रसार से जुड़े कदम उठाने के लिए दबाव बनाना था। उस समय अमेरिकी प्रशासन ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि इन प्रतिबंधों से दोनों देशों को आर्थिक और राजनीतिक लागत चुकानी पड़ सकती है।

इन प्रतिबंधों का भारत पर निश्चित रूप से असर पड़ा, लेकिन नई दिल्ली ने अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने एक ओर अमेरिका के साथ संवाद का रास्ता खुला रखा, दूसरी ओर अपने कारोबारी संबंधों को विभिन्न देशों के साथ मजबूती से बनाए रखा। भारत की दृढ़ता और कूटनीतिक लचीलेपन का परिणाम यह हुआ कि प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हुई। 1999 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के लिए प्रतिबंधों में कुछ राहत की गुंजाइश बढ़ाई, और 2000 में एक रक्षा विनियोग कानून के जरिए राष्ट्रपति को इन प्रतिबंधों को माफ करने का व्यापक अधिकार मिल गया।

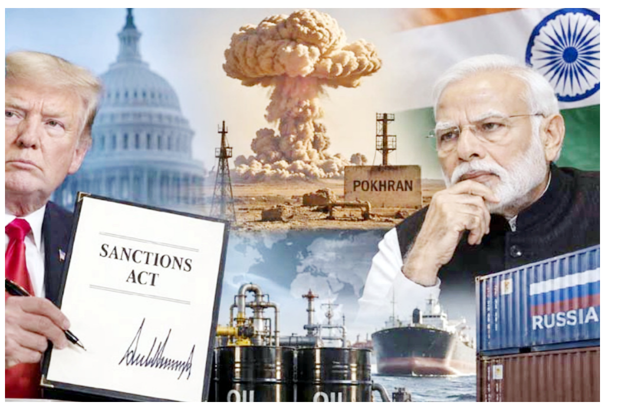

इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संवाद लगातार आगे बढ़ता रहा। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत बनी। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन ने भी भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। आखिरकार, 22 सितंबर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए ग्लेन संशोधन प्रतिबंधों को भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए माफ कर दिया। अमेरिकी सरकारी दस्तावेज में इसे दोनों देशों के साथ अप्रसार संबंधी मुद्दों पर कम दबाव वाले माहौल में जुड़ने की नीति के रूप में दर्ज किया गया है।

इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे रणनीतिक नजदीकी बढ़ी और 2008 में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने इन संबंधों को एक नया आयाम दिया। 1998 से 2001 तक का यह अनुभव यह दिखाता है कि प्रतिबंधों के दौर में भी भारत ने अपनी नीतिगत स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा। आज जब रूस से भारतीय ऊर्जा खरीद को लेकर फिर से दबाव की स्थिति बन रही है, तो 1998 का यह अनुभव हमें सिखाता है कि रणनीतिक धैर्य और निरंतर संवाद हमेशा महत्वपूर्ण होता है, हालाँकि मौजूदा कानून के तहत संभावित टैरिफ की वास्तविक दर और दायरा अमेरिकी प्रशासन के आगे के फैसलों पर निर्भर करेगा।

कृषि विश्वविद्यालय में 28 से 30 तक यूथ इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं वित्त मंत्री शुभारंभ समारोह में रहेंगे मौजूद

सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 28 से 30 सितंबर 2026 तक छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। राज्य में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले इस यूथ कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से लगभग एक हजार से अधिक नवोन्मेषी युवा उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस तीन दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन 28 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के

राज्यपाल श्री रामेन डेका करेंगे तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा। यूथ कॉन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी तथा शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा। यूथ कॉन्क्लेव में शामिल होने के इच्छुक युवा छात्र एवं उद्यमी 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन करवा सकते हैं।

यूथ कॉन्क्लेव 2026 में नवाचार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल है। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इस मंच के माध्यम से नवीन विचारों, अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों को व्यावसायिक अवसरों एवं सफल उद्यमों में परिवर्तित करने के साथ-साथ राज्य में एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

ताजा खबर
संक्षिप्त

रावघाट- ताड़ोकी विद्युतीकृत ब्रॉडगेज सेक्शन का स्पीड ट्रायल

रायपुर। दल्लीराजहराङ्क रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के ताड़ोकीङ्करावघाट सिंगल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉडगेज सेक्शन का निरीक्षण सुमीत सिंघल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) ने किया । सिंघल मंगलवार को सीआरएस स्पेशल ट्रेन से ताड़ोकी से रावघाट सेक्शन का स्पीड ट्रायल भी किया गया । इस अवसर पर मुदित भटनागर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) मुख्यालय बिलासपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर दयानंद, रेल विकास निगम लिमिटेड से सरोज कांता पात्रा, पीईडी ईस्ट-आरवीएनएल, भावेश पांडे-सीपीएम/आरवीएनएल/ रायपुर कन्हैया गोयल/ एजीएम/ आरवीएनएल/रायपुर सहित संबंधित वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित रहे। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा किया गया निरीक्षण एवं गति परीक्षण नई रेल लाइन के कमीशनिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस दौरान रेल लाइन, पुल-पुलियों, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग एवं अन्य संरक्षा तथा तकनीकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेलखंड की परिचालन क्षमता एवं संरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। बहुप्रतीक्षित दल्लीराजहरा रावघाट रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। वर्तमान में दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक यात्रियों को रेल की सुविधा मिल रही है । ताड़ोकी ङ्क रावघाट सेक्शन में ट्रेन परिचालन से आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन के बेहतर एवं सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होंगे।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा ने लहराया सफलता का परचम

रायपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा ने संपूर्ण प्रदेश में अपना परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की राज्य स्तरीय एनएसएस पुरस्कार चयन सूची में विश्वविद्यालय और उससे जुड़ी संस्थाओं तथा स्वयंसेवकों ने कुल पांच पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस शानदार उपलब्धि में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय स्तर की श्रेणी में पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर सरगुजा संभाग का गौरव बढ़ाया है। संस्थागत श्रेणी में सरगुजा जिले के सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं महाविद्यालयीन स्वयंसेवक श्रेणी में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर के शिवम शर्मा और शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जशपुर नगर की कु. नेहा यादव ने बाजी मारी है। इसके अलावा विद्यालय स्तर की स्वयंसेवक श्रेणी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिना (सूरजपुर) की कु. मीना राजवाड़े का चयन हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 सितम्बर को रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ इन सभी उत्कृष्ट संस्थाओं और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत सरगुजा संभाग के छह जिलों में 158 इकाइयां संचालित हैं, जो जमीनी स्तर पर समाजसेवा और सामुदायिक विकास के कार्यों में जुटी हुई हैं।

गणित के डर को आकर्षण में शिक्षण पर शिक्षकों को मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर, रायपुर में मंगलवार को 'द आर्ट ऑफ टीचिंग मैथेमैटिक्सः फ्रॉम फियर टू फैसिनेशन विषय पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को गणित शिक्षण की ऐसी नवीन, गतिविधि - आधारित और रचनात्मक विधियों से परिचित कराना रहा, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए गणित को सरल, रोचक और आनंददायक बनाया जा सके। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में गणित को केवल पाठ्यपुस्तक, सूत्रों और गणनाओं तक सीमित न रखते हुए दैनिक जीवन, अनुभव, गतिविधियों और रचनात्मकता से जोड़कर पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इस तरह की शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों में गणित के प्रति रूचि और जिज्ञासा बढ़ाने के साथ-साथ तार्किक सोच विकसित करने में भी सहायक हो सकती है।

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत

तीज मिलन उत्सव: सीएम साय ने कहा माताओं-बहनों सौभाग्य अखंड रहे

रायपुर। नवा रायपुर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा की ओर से तीज मिलन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह और बहू ऐश्वर्या सिंह समेत प्रदेशभर से महिलाएं और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

तीज मिलन उत्सव में मुख्यमंत्री साय का संबोधन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीज मिलन उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि तीज के अवसर पर विवाहित माताएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी का सौभाग्य अखंड रहे।

सीएम साय ने कहा कि आज यहां छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही समाज में माताओं का विशेष महत्व रहा है। त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या सतयुग, हर काल में नारी के सम्मान को महत्व दिया गया है। हमारी

सरकार भी माताओं-बहनों के सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है। पौने तीन साल में 31 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है। जब मैं कार्यक्रमों में जाता हूं तो माताओं-बहनों के चेहरों पर अलग तरह की खुशी दिखाई देती है। आज महिलाओं को अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए पति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, उनके खाते में हर महीने एक हजार रुपये की राशि पहुंच रही है।

ढाई साल में बनाए गए 18 लाख से अधिक आवास

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ काम कर रही है। ढाई साल में छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। हर परिवार तक बिजली, नल का पानी और गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देश ने पहले भी महामारियों का सामना किया है, लेकिन उस समय वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी वैक्सीन तैयार की और 140 करोड़ देशवासियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया।

13 लाख से अधिक बहनें बनीं लखपति दीदी: सीएम साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगातार देश की सेवा करते रहें और देशवासियों का इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें, यही कामना है। सरकार की योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 13 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बनी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिक व संस्था को 'श्रम यशस्वी पुरस्कार' से नवाजा जाएगा

पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, आवेदन 5 अक्टूबर तक आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2025-26 से नवाजा जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के लिए चयनित श्रमिक अथवा संस्था को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा आगामी 5 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यह पुरस्कार उन श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किया हो। विशेष तौर पर ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रभावी उपाय किए गए हों और जिनके फलस्वरूप पूरे वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना घटित न हुई हो। इस संबंध में बताया गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले श्रमिकों एवं संस्थाओं को भी पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। ऐसे प्रयास, जिनसे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो, पुरस्कार के लिए महत्वपूर्ण आधार होंगे।

श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों एवं संस्थाओं से 5 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक श्रमिक एवं संस्थाएं श्रम विभाग की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीतंउमअरंलंजमण्बहण्हवअण्पदध्संदातंदर्ेंचग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित नियम, पात्रता, प्रक्रिया एवं आवेदन प्रपत्र भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

'श्रम यशस्वी पुरस्कार' श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्टता, श्रमिक सुरक्षा और स्वस्थ कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

पुरस्कार के माध्यम से उन श्रमिकों एवं संस्थाओं के प्रयासों को सार्वजनिक पहचान मिलेगी, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और सुरक्षित कार्य वातावरण के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

PV ऐप से फसल गिरदावरी का पटवारियों ने किया बहिष्कार

रायपुर। खरीफ फसल गिरदावरी 2026-27 को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने (फसल भौतिक सत्यापन) ऐप के माध्यम से फसल गिरदावरी कराए जाने का पूर्णतः बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और भू-अभिलेख संचालनालय के संचालक को ज्ञापन सौंपा गया है।

संघ के अनुसार, शासन ने खरीफ गिरदावरी वर्ष 2026-27 के लिए 17 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक समय निर्धारित किया था। इसके तहत प्रदेश के सभी पटवारी छ्ष्टस् और ऑनलाइन माध्यम से गिरदावरी का कार्य कर रहे थे। संघ का आरोप है कि अचानक बिना पूर्व सूचना के ऑनलाइन फसल एंट्री को पटवारी आईडी से बंद कर दिया गया और 18 सितंबर को क्क्ङ्क ऐप के माध्यम से फसल गिरदावरी करने का निर्देश जारी कर दिया गया। पटवारी संघ ने अपने ज्ञापन में छ्ष्टस् के नक्शे में तकनीकी खामियों का

भी उल्लेख किया है। संघ का कहना है कि वर्तमान छ्ष्टस् का नक्शा करीब तीन वर्ष पुराना है और मौके पर विभाजित किए गए लाखों नक्शे तकनीकी खामियों के कारण छ्ष्टस् में शामिल नहीं हो पाए हैं। संघ का कहना है कि जिन खसरों का नक्शा विभाजन नहीं हुआ है, उन्हें मौके पर किसान की सहमति के बिना किस तरह चिन्हित किया जाएगा, यह भी एक बड़ी समस्या है। पटवारियों ने राजस्व संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस तरह दबावपूर्वक काम कराए जाने को अनुचित बताया है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चा

375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन : उप मुख्यमंत्री

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चाविकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया।

बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

विधायक सुनील सोनी की मौजूदगी में हुई संध्या आरती

वरिष्ठ पत्रकारों ने की भगवान गणेश की आराधना

रायपुर। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित गणेश उत्सव में मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने सहभागिता करते हुए भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी की विशेष मौजूदगी में विधिवत पूजा-अर्चना एवं संध्या आरती की गई।

रायपुर प्रेस क्लब द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा की थीम पर मनाया जा रहा है। उत्सव को पत्रकार बिरादरी के सामूहिक सहभागिता पर्व के रूप में मनाते हुए अलग-अलग दिनों में विभिन्न वर्गों एवं विधाओं से जुड़े पत्रकार साथियों को भगवान गणेश की आराधना का अवसर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर संध्या आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारिता की पुरानी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच आत्मीय संवाद एवं मिलन का अवसर भी बना। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यादव, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश

जांगड़े सहित वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा, रामावतार तिवारी, ठाकुर राम साहू, राजेश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रशांत शर्मा, मंजूषा शर्मा, शशांक खरे, सजीव वर्मा, वीरेंद्र शर्मा,कौशल तिवारी, नरेंद्र बंगाले, राजेंद्र निगम, शंकर चंद्राकर, टीकम वर्मा, प्रह्लाद दमहे, बल्ला तिवारी, चंद्रकांत दौंड, अविनाश चौबे,रतन पांडे, शगुफ्ता शिरीन, कमलेश गोगिया, मनीष वोरा एवं सनत तिवारी, पीयूष मिश्रा, प्रदीप साहू, कमलाकांत , विजय यादव,विद्याभूषण सिन्हा ,पवन ठाकुर, सैयद सलमा,सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी ने भगवान गणेश की आरती में शामिल होकर प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ संवाद भी किया।

प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष का अवसर हम सभी के लिए गौरव का विषय है। इसी भावना के साथ इस वर्ष गणेश उत्सव को पत्रकारिता की परंपरा और पत्रकार बिरादरी की सहभागिता से जोड़ा गया है। वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए अनुभव और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण अवसर है।

रायपुर प्रेस क्लब की ओर से सभी पत्रकार साथियों से आगामी आयोजनों में सहभागी बनने और भगवान गणेश की संध्या आरती में शामिल होने का आह्वान किया गया।

वीडियो जर्नलिस्ट साथियों ने भी की भगवान गणेश की आराधना

रायपुर। प्रेस क्लब गणेश उत्सव में रविवार को वीडियो जर्नलिस्ट साथियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वीडियो पत्रकार साथियों ने प्रेस क्लब में विराजे भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर संध्या आरती में हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा एवं खरे तथा वीडियो जर्नलिस्ट साथी रविंद्र नागलकर, विश्वनाथ साहू, पुनीत सोनकर, मुकेश वर्मा, महेंद्र नामदेव, खोमेन्द्र देशमुख, आरिफ खान, नरेश नवरंग, राकेश गौरखेड़े, इमरान कुरैशी, दीपक बावनकर, विक्की पंजवानी, लखन शर्मा, राजेंद्र चौधरी, महेश साहू, मनोज साहू, रमाशंकर केसरवानी, मिथलेश साहू, धरम साहू, दुर्गेश साहू, मनीष हरपाल, अनूप साहू एवं सूर्यकांत गौतम सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

टेस्ट डेब्यू के इतिहास में 123 साल बाद भी अजेय है फॉस्टर का कीर्तिमान

लंदन। टी20 क्रिकेट के बढ़ते रुझान के बाद भी माना जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में ही किसी बल्लेबाज की असली परीक्षा होती है। इसका कारण है कि टेस्ट क्रिकेट में रन बनना आसान नहीं होता और इसके लिए धैर्य व संयम की जरुरत होती है।

इसी कारण क्रिकेट इतिहास में आज तक केवल सात बल्लेबाज ही ऐसे हुए हैं जो अपने डेब्यू मैच में दोहरा शतक लगा पाये हैं। इसमें पहले नंबर पर इंग्लैंड के आर. ई. फॉस्टर हैं। साल 1903 में सिडनी के ऐतिहासिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए फॉस्टर ने अपने पहले ही मैच में 287 रनों की बड़ी पारी खेली थी। इस मैच में फॉस्टर ने 419 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं दिया। अपनी इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 37 शानदार चौके लगाए थे। इसके बाद से ही आज तक कोई भी बल्लेबाज पिछले 123 साल में डेब्यू टेस्ट में फॉस्टर से बड़ी पारी नहीं खेल पाया है।

फॉस्टर के इस अद्भुत रिकॉर्ड के लगभग सात दशक बाद, यानी 1972 में, वेस्टइंडीज के करिश्माई बल्लेबाज लॉरेंस रो ने डेब्यू मैच में दोहरा शतक लगाया था। किंग्स्टन के अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए लॉरेंस रो ने 214 रनों की बेहद आकर्षक पारी खेली। 427 मिनट की अपनी बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 19 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं 1980 के दशक में जब श्रीलंका की टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कदम जमा रही थी, तब उनके सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन कुरुप्पू ने एक ऐसी पारी खेली जो क्रिकेट जगत में मिसाल बन गई। अप्रैल 1987 में कोलंबो के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कुरुप्पू ने संयम और धैर्य का ऐसा नजारा पेश किया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। उन्होंने 548 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 201 रन बनाए। 777 मिनट (लगभग 13 घंटे) तक क्रीज पर टिके रहकर कुरुप्पू ने 24 चौके जड़े। 36.67 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी टेस्ट इतिहास की सबसे लंबी और जुझारू डेब्यू पारियों में शुमार है।

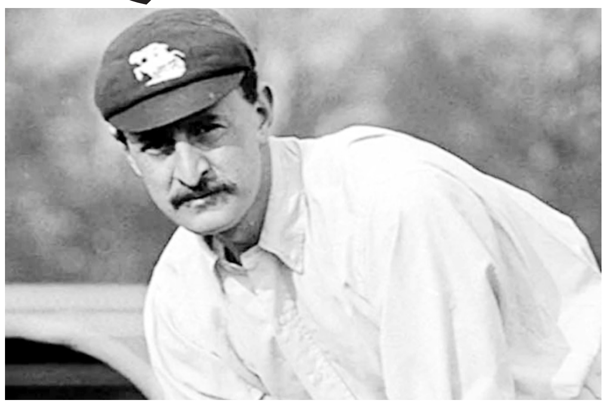

सदी के बदलने के साथ ही नए दौर के क्रिकेटरों ने भी इस खास सूची में अपना नाम दर्ज कराया। न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंकलेर ने 1999 के बॉक्सिंग डे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ वेलिंगटन के मैदान पर 447 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 214 रनों की तूफानी पारी खेली। 534 मिनट तक क्रीज पर रहकर 47.87 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए उनके ये रन वेस्टइंडीज के खौफनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने आए थे, जिसने इस पारी के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया।

इस खास क्लब के पांचवें और आखिरी सदस्य बने दक्षिण अफ्रीका के जाक रुडॉल्फ। अप्रैल 2003 में चट्टोग्राम के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए रुडॉल्फ ने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। उन्होंने 383 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 222 रनों की आक्रामक पारी खेली। 521 मिनट की अपनी इस मैराथन पारी में उन्होंने 29 चौके और 2 छक्के लगाए, और उनका स्ट्राइक रेट 57.96 का रहा।

महत्वपूर्ण ख़बर

न्यूजीलैंड की 16 सदस्यीय टीम घोषित, सैंटनर संभालेंगे कमान

- वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित की है। मिशेल सेंटनर टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि एडम मिल्न और माइकल ब्रेसवेल की वापसी हुई है। रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण बाहर हैं। फिन एलन और टिम सीफर्ट की सलामी जोड़ी भी फिर साथ दिखेगी।

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर टीम की अगुआई करेंगे।

आईपीएल का सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रहे लक्ष्मी मित्तल और अदार पूनावाला

मुम्बई। स्टील किंग लक्ष्मी एन मित्तल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला ने मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को खरीदने की मेगा डील लगभग पूरी कर ली है। इस बड़े अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ऐतिहासिक सौदा लगभग 1.65 अरब डॉलर (करीब 15,838.63 करोड़) में तय हुआ है, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे बड़े सौदों में से एक है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस अधिग्रहण को 17 सितंबर को ही अपनी मंजूरी दे दी थी। ऐसे में अब इस डील के पूरा होने की कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मित्तल और पूनावाला के इस अधिग्रहण पैकेज में केवल राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के मालिकाना अधिकार वाली दो विदेशी क्रिकेट टीमें दक्षिण अफ्रीका की टी-20 लीग 20 में भाग लेने वाली पार्ल रॉयल्स और वेस्टइंडीज कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में खेलने वाली बारबाडोस रॉयल्स भी अब मित्तल और पूनावाला के मालिकाना अधिकार में आ जाएंगी। यह विस्तार दर्शाता है कि यह अधिग्रहण सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक क्रिकेट लीगों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह महत्वाकांक्षी सौदा ब्रिटेन में पंजीकृत निवेश कंपनी वेस्टव्यू क्रिकेट लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिसका स्वामित्व मित्तल परिवार के पास है। इस सौदे में पूनावाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक प्रमुख हिस्सेदार है। इस डील के तहत, मित्तल परिवार वेस्टव्यू क्रिकेट के माध्यम से फ्रेंचाइजी समूह की लगभग 75 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगा, जबकि अदार पूनावाला की हिस्सेदारी करीब 18फीसदी होगी। मौजूदा निवेशकों में शामिल मनोज बदाले के पास अपनी लगभग 7फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रहने की उम्मीद है। इस सौदे की घोषणा इस साल की शुरूआत में ही लगभग 1.65 अरब डॉलर के एंटरप्राइज वैल्यू पर की गई थी, जो इसकी विशालता और क्रिकेट जगत में इसके महत्व को रेखांकित करता है। यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते से पहले, अमेरिकी निवेशकों के नेतृत्व वाले एक समूह ने भी राजस्थान रॉयल्स को खरीदने का असफल प्रयास किया था, तब फ्रेंचाइजी समूह का मूल्यांकन लगभग 1.63 अरब डॉलर आंका गया था। मित्तल और पूनावाला जैसे दिग्गज उद्योगपतियों का राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ना फ्रेंचाइजी के लिए एक नया अध्याय खोलेगा और टीम को वित्तीय तथा रणनीतिक रूप से और भी मजबूत करेगा।

मैच फिक्सिंग के आरोपों पर वंश बेदी ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली। वंश बेदी ने डीपीएल में मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए रिपोर्ट्स को झूठा और मानहानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है और उनकी कानूनी टीम ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में कथित भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से जुड़े विवाद के बीच सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है। बेदी ने सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर उनके नाम को कथित मैच फिक्सिंग के मामले से जोड़ने वाली खबरों को झूठा और मानहानिकारक बताया है।

जहीर को धोनी की सलाह पर सीएसके ने बनाया कोच ?

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया मुख्य कोच बनाया है। माना जा रहा है कि सीएसके के इस फैसले के पीछे टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अहम भूमिका होगी। धोनी की सलाह पर ही सीएसके ने जहीर को कोच की जिम्मेदारी सौंपी होगी। यह नियुक्ति फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जहीर ने उस लंबे कोचिंग कार्यकाल की जिम्मेदारी ली है जो पिछले कई वर्षों से टीम की सफलता का सबसे मजबूत आधार रहा है। इसी कारण जब टीम के लिए नए कोच की तलाश शुरू हुई, तो कई विदेशी और देसी दिग्गजों के बड़े-बड़े नाम दौड़ में शामिल थे पर इसके बाद भी सीएसके ने जहीर के अवसर दिया।

सीएसके के क्रिकेट प्रबंधन पर धोनी का प्रभाव है, ऐसे में सोच थी कि टीम की कमान किसी ऐसे भारतीय दिग्गज को सौंपी जाए जो घरेलू स्तर पर युवाओं की नब्ज पहचानता हो। वहीं जहीर न केवल एक चतुर रणनीतिकार हैं, बल्कि खेल की उनकी समझ असाधारण है। धोनी भली-भांति जानते हैं कि टीम इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहाँ नए और युवा खिलाड़ियों को तैयार करना है। ऐसे में जहीर से बेहतर क्रिकेटिंग दिमाग वाला कोच कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता था। पूर्व में अन्य बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ काम करने के जहीर के रणनीतिक अनुभव का लाभ भी सीएसके को मिलेगा।

धोनी और जहीर का रिश्ता महज एक कप्तान और गेंदबाज का नहीं रहा है। यह अटूट विश्वास और सम्मान की कहानी है। भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर, विशेषकर 2011 के ऐतिहासिक विश्व कप अभियान में इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, जहाँ जहीर भारत के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे थे। मैदान पर जब भी टीम मुश्किल में होती थी, धोनी बिना सोचे गेंद जहीर के हाथ में थमा देते थे।

ऐसा ही एक यादगार लम्हा इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मुकाबले का है, जहाँ एंड्रयू स्ट्रॉस भारतीय गेंदबाजों पर हावी थे। धोनी ने जहीर को गेंद थमाई और उन्हें अपनी मजी से फील्डिंग लगाने की पूरी आजादी दी। जहीर ने अपनी रणनीति से स्ट्रॉस और इयान बेल को लगातार गेंदों पर आउट कर मैच का पासा पलट दिया था।

बढ़ गई भारत के मेडल की संख्या, एक दिन में देश के नाम हुए 4 मेडल, मीराबाई चानू ने बिखेरा जलवा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. अब तक भारत एशियन गेम्स में भारत ने कुल 10 मेडल अपने नाम कर लिए हैं. आज भारत सुबह-सुबह इंडिया को दो मेडल हासिल हुए. भारत को पहले महिला स्कीट टीम इवेंट में मेडल मिला और फिर भारोत्तोलन में देश को मीराबाई चानू ने मेडल दिलाया. तो आइए जानते हैं कि भारत को किन खिलाड़ियों ने आज मेडल दिलाया और अब तक देश के कितने मेडल हो चुके हैं और किन खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है.

आज यानी एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन परिनाज धालीवाल, रजिया ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने एशियन गेम्स 2026 में भारत को कांस्य पदक दिलाया है. इसके साथ ही भारत के मेडल की संख्या में भी इजाफा हो गया. इन तीनों एथलीटों ने बुधवार को महिला स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है. इसके साथ ही इन तीनों खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है. आज तीन दिनों के क्वालिफिकेशन राउंड के बाद परिनाज, रजिया और माहेश्वरी ने क्वालिफिकेशन में कुल 331 का स्कोर किया और तीसरा स्थान हासिल किया. चीनी टीम चे यूफेई, जियान यिटिंग और जियांग चाओयू ने 347 के स्कोर के साथ स्वर्ण और कजाकिस्तान की असेम ओरिनबे, जोया पिस्कुन और एडेल सदाकबायेवा ने 336 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता. देश को अनंत नरुका, मारियाज अहमद खान और भावतेग सिंह की तिकड़ी ने एशियन गेम्स 2026 में भारत को कांस्य पदक दिलाया है.

कारोबार

भारतीय अर्थव्यवस्था में दम

फिच ने भी बढ़ाया एफ27 में वृद्धि दर का अनुमान

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष (ऋ27) के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। जून तिमाही में दर्ज की गई 7.8 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और समग्र लचीलेपन को देखते हुए यह संशोधन किया गया है।

हालांकि, एजेंसी का अनुमान है कि बढ़ती महंगाई और आपूर्ति संबंधी चिंताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी अक्तूबर मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी कर सकता है। फिच रेटिंग्स के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ दर ने यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों का मुकाबला करने में सक्षम है। वर्ष 2026 की पहली छमाही में व्यापार की शर्तों में गिरावट और अमेरिका-ईरान युद्ध के प्रभाव के बावजूद देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है।

रेटिंग एजेंसी का मानना है कि निजी निवेश के मोर्चे पर स्थिति काफी बेहतर दिख रही है। फिच का अनुमान है कि देश में निजी निवेश में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, जुलाई महीने में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि सालाना आधार पर 19 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में मजबूत मांग को दशार्ती है।

यूपी ट्रेड शो का 25 सितंबर से होगा आगाज, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, कारोबारी और निर्यात क्षेत्र को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस)-2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर से शुरू होने वाले इस पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि मेले का समापन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यूपीआईटीएस की केंद्रीय थीम अद्वितीय सोर्सिंग का अद्भुत मंच... रखी गई है। थीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के कारोबारियों, निवेशकों, खरीदारों तथा उद्योग जगत के लिए एक बड़े सोर्सिंग हब के रूप में प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया है। आयोजन में प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के साथ-साथ पारंपरिक उत्पादों, आधुनिक तकनीक, निर्यात क्षमता, कृषि आधारित उद्योग और उभरते कारोबारी क्षेत्रों को भी प्रमुखता दी जाएगी।

आरबीआई बढ़ती महंगाई के चलते 2026 में दो बार बढ़ा सकता है ब्याज दरः रिपोर्ट

नई दिल्ली। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नोमुरा के ग्लोबल मैक्रो रिसर्च प्रमुख रॉब सुब्बारमन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महंगाई का दबाव बढ़ने से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाली दोनों मौद्रिक नीति बैठकों (अक्टूबर और दिसंबर) में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि आने वाले महीनों में महंगाई 6 प्रतिशत के पार जा सकती है। सुब्बारमन ने कहा कि भारत के पास वैश्विक निवेश आकर्षित करने और वैश्विक वैल्यू चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

भारत के पास विभिन्न क्षेत्रों में बड़े अवसर हैं, लेकिन अगर अमेरिका और उत्तर-पूर्व एशिया में एआई निवेश की कहानी बहुत मजबूत बनी रहती है, तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भारत पीछे रह सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक पूंजी आकर्षित कर सकता है। एफसीएनआर-बी जमा में उम्मीद से बेहतर प्रवाह देखने को मिला है और मजबूत भुगतान संतुलन अधिशेष की भी संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक पर नजर

सुब्बारमन ने बताया कि बाजारों की नजर संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाली कूटनीतिक गतिविधियों और इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक पर है। वैश्विक मौद्रिक नीति पर सुब्बारमन ने कहा कि इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कम से कम एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो संभवतः दिसंबर में हो सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है तो दरों में और बढ़ोतरी का जोखिम है। उन्होंने कहा कि एफओएमसी के ताजा अनुमान व्यापक रूप से सख्त मौद्रिक नीति की दिशा की ओर संकेत करते हैं। 18 नीति निमार्ताओं में से 12 ने इस साल एक और दर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है, जबकि चार ने दो और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और केवल दो ने आगे किसी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं की है।

नीतिगत ब्याज दर बढ़ोतरी

अमेरिकी फेड ने पिछले सप्ताह अपनी नीतिगत ब्याज दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में कर दिया था। सुब्बारमन ने कहा कि बाजारों को उम्मीद है कि कूटनीति वैश्विक तनाव और अमेरिका-चीन व्यापार प्रतिबंधों को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे ऊर्जा की लागत और लंबी अवधि की बॉन्ड यील्ड में कमी आ सकती है।

उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी दबाव बनाने की क्षमता है, क्योंकि ऊंची ऊर्जा कीमतें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन की ऊंची कीमतें डाउनस्ट्रीम तेल कारोबार पर दबाव डाल रही हैं। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत करीब 4.50 डॉलर और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर के करीब 6.50 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गई है।

लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा संस में होगा फेरबदल?

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा समूह में अंदरूनी स्तर पर खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है। होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने को लेकर जहां शीर्ष स्तर पर मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा लिस्टिंग से बचने के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने टाटा संस को कई अलग-अलग इकाइयों में बांटकर उसका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई की ओर से टाटा संस का पंजीकरण रद्द करने का आवेदन खारिज किए जाने के बाद कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना काफी बढ़ गई है। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इसके पक्ष में नहीं हैं।

सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 23,350 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार की शुरूआत मजबूती के साथ हुई। शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंक चढ़कर 74,640.85 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 23,350 के ऊपर कारोबार करता दिखा।

बजाज समूह की दोनों कंपनियों और एशियन पेंट्स के शेयरों में करीब 2% तक की तेजी ने बाजार को सहारा दिया। हालांकि, इससे पहले मंगलवार को बाजार दिन के निचले स्तर से रिकवरी बनाए रखने में विफल रहा था और कमजोर होकर बंद हुआ था।

शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स 74,640.85 पर रहा, जो पिछले स्तर से 111.77 अंक या 0.14% ऊपर है। निफ्टी 23,367 पर था, जिसमें 38 अंक या 0.16% की बढ़त दर्ज हुई। कच्चे तेल की गिरती कीमतों और एशियाई मुद्राओं में व्यापक सुधार के चलते बुधवार को शुरूआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 95.57 पर पहुंच गया। बाजार में कुछ प्रमुख शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बजाज ट्विन्स और एशियन पेंट्स करीब 2% तक चढ़े, जिससे शुरूआती कारोबार में प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली।

मंगलवार को घरेलू बाजार दबाव में रहा। दिन के निचले स्तरों से आई रिकवरी टिक नहीं पाई और अंत में प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। इससे बाजार की निकट अवधि की दिशा को लेकर सावधानी बनी हुई है। विश्लेषकों के मुताबिक, निफ्टी निकट अवधि में कंसोलिडेशन यानी सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव कर सकता है। आने वाले कारोबारी सत्रों में इसके 23,115 से 23,650 के व्यापक दायरे में रहने की संभावना बताई गई है।

तकनीकी चार्ट पर निफ्टी ने दैनिक आधार पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यह बाजार में पहले बनी तेजी की गति कमजोर पड़ने का संकेत माना जाता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे के मुताबिक, बाजार का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है और निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,300 पर है। यदि यह स्तर टूटता है तो इंडेक्स के 23,000 तक खिसकने का दबाव बन सकता है। तकनीकी नजरिए से 23,400 निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस है। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिकाऊ बढ़त बनाने में सफल रहता है तो अगला लक्ष्य 23,600 और उससे ऊपर के स्तर हो सकते हैं। इसलिए आने वाले सत्रों में 23,300 और 23,400 के स्तर बाजार की दिशा समझने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं?

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में खास बदलाव नहीं था। अस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी लगभग स्थिर रहा। वहीं, हॉन्ग कॉन्ग का हेंगसेंग 0.8% और शंघाई कंपोजिट 0.4% नीचे रहा। दूसरी ओर, यूरो स्टॉक्स फ्यूचर्स में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई।

आगे क्या देखें?

घरेलू बाजार के लिए अब निवेशकों की नजर निफ्टी के 23,300 सपोर्ट और 23,400 रेजिस्टेंस पर रहेगी। इन स्तरों के आसपास होने वाली गतिविधि निकट अवधि में बाजार की दिशा के बारे में संकेत दे सकती है। फिलहाल तकनीकी संकेत कंसोलिडेशन और सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं।

'मैडम आपके खाते में आतंकियों ने 7 करोड़ जमा किए'

भोपाल में 'डिजिटल अरेस्ट' कर महिला से 35 लाख रुपये की ठगी

भोपाल। गोविंदपुरा इलाके में साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और उसे धमकाया कि उसके नाम से बैंक खाते में आतंकियों ने सात करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसी का डर दिखाकर ठगों ने 35 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने वीडियो कॉल पर महिला को पुलिस मुख्यालय जैसा माहौल दिखाया और कहा कि उसे 45 दिन के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चों को भी गिरफ्तारी की धमकी दी।

डर के कारण महिला ने अपनी जमा पूंजी और एफडी की रकम आरोपितों के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। बाद में लगातार पैसों की मांग होने पर महिला को ठगी का एहसास हुआ। साइबर क्राइम की जांच रिपोर्ट के आधार पर गोविंदपुरा पुलिस ने सोमवार को केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, साकेत नगर निवासी उमा समद्दार एलआइसी और पोस्ट आफिस एजेंट हैं। 23 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और महिला से कहा कि उसके नाम से एचडीएफसी बैंक में खाता खुला है।

महिला ने घबराकर जमा कर दी रकम

इस खाते में आतंकियों ने सात करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली है। ऑनलाइन ठगों ने महिला से कहा कि गिरफ्तारी से बचना है तो अपनी जमा पूंजी बताए गए खातों में जमा कर दें, जिसे बाद में वापस कर दिया जाएगा। धमकी से घबराई महिला ने 29 सितंबर 2025 को 21 लाख 57 हजार 815 रुपये बताए गए खाते में जमा कर दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसकी एफडी तुड़वाकर दूसरे खाते में रकम जमा करने को कहा। महिला ने 15 अक्टूबर 2025 को करीब आठ लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपितों ने फिर रकम मांगी।

महिला ने उधार लेकर साढ़े तीन लाख रुपये और बाद में एक लाख रुपये भी बताए गए खातों में जमा कर दिए। इस तरह आरोपितों ने उससे करीब 35 लाख रुपये ऐंठ लिए। लगातार रकम मांगने पर महिला को संदेह हुआ और उसने साइबर क्राइम में शिकायत की। जांच में बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, रकम जमा करने की रसीदें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए।

साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने 15 लाख होल्ड

एएसआई संजय शुक्ला ने बताया कि महिला ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत की थी। कार्रवाई के दौरान करीब 15 लाख रुपये खाते में होल्ड कराए गए थे। अब रकम चाहिए तो कोर्ट में एफआइआर की कापी लगेगी , इसलिए साइबर क्राइम की रिपोर्ट मिलने के बाद गोविंदपुरा पुलिस ने पूरे एक साल बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के आधार पर आरोपियों की पहचान और रकम के ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है।

शहडोल में निर्माण के दौरान भरभराकर गिरी पुरानी दुकान, मलबे में दबे दो मजदूर

शहडोल। शहर के बीचोंबीच बस स्टैंड के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मुख्य मार्ग किनारे स्थित पुरानी दो मंजिला इलेक्ट्रानिक्स दुकान में निर्माण कार्य के दौरान लोहे का गार्डर अचानक टूट गया, जिससे निमार्णाधीन हिस्सा भरभराकर गिर गया। मलबे में दबकर दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

निर्माण कार्य के दौरान अनदेखी

जानकारी के अनुसार भवन काफी पुराना है और अंदर दुकान का संचालन जारी था, इसी बीच भीतर तोड़फोड़ कर नया निर्माण कराया जा रहा था। बताया गया कि ठेकेदार ने पहले ही गार्डर पर ज्यादा भार पड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन काम नहीं रोका गया। हादसे के बाद साथी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकाला।

घायलों की पहचान औढेरा निवासी हीरालाल रैदास और लाला सिंह के रूप में हुई है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा को देखते हुए भवन के खतरनाक हिस्से को जेसीबी से ढहा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे।

सूर्यास्त के बाद हुई थी महिला की गिरफ्तारी

अब चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज

बालाघाट। जिले में किरनापुर थाने में चोरी के शक में महिला से मारपीट के मामले में निलंबित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद एसपी मिश्रा ने सात सितंबर को संबंधित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। डीएसपी (महिला सुरक्षा शाखा) प्रतिष्ठा राठौड़ के नेतृत्व में गठित एसआईटी को दो सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

एसआईटी के प्रतिवेदन के अनुसार, संबंधित महिला को न्यायालय में पेश किए जाने से पहले नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। न्यायालय में पेशी के दौरान अधिवक्ता भी मौजूद थे। उस समय न्यायालय के समक्ष मारपीट अथवा शारीरिक चोट से संबंधित कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। इसके बाद आवेदिका ने थाने में जबरन स्वीकारोक्ति कराने और असंवैधानिक रूप से हिरासत में रखे जाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की।

एसआईटी की जांच में मुख्य विधिक त्रुटि के रूप में यह तथ्य सामने आया कि सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद की गई थी। रोजनामचा में प्रविष्टि किए जाने में भी विलंब पाया गया। जांच दल द्वारा संकलित साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इन प्रक्रियागत उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद संबंधित चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध महिला थाना बालाघाट में अपराध दर्ज किया गया है।

एमपी में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल

भोपाल। यदि आपको बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या काम पूरा करना है, तो उसे अगले 3 दिनों (बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार) के भीतर निपटा लें। इसके बाद अगले 5 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के तुरंत बाद बैंक कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल के कारण शाखाओं में काम ठप रहेगा।

हड़ताल से कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित?

5 दिनों तक बैंक बंद रहने से आम जनता और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान मुख्य रूप से कई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसकी वजह से चेक क्लियरेंस प्रक्रिया रुक जाएगी। शाखाओं से कैश जमा और निकासी ठप रहेगी। साथ ही बैंकों में प्रशासनिक और ड्राफ्ट संबंधी काम लटक जाएंगे।

बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या हैं?

वर्तमान में बैंकों में हर दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी होती है। बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगें हैं कि सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू की जाए। शनिवार की छुट्टी के बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने का प्रस्ताव है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ ही स्केल-क्ष लागू करने की मांग रखी है।

3 चरणों में आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कॉर्डिनेटर वी.के. शर्मा के अनुसार, सरकार के साथ कई दौर की वार्ता होने के बावजूद 5-डे वीक की वाजिब मांग को टाला जा रहा है। सरकार के टालमटोल वाले रवैये के विरोध में यूनियनों ने तीन चरणों में आंदोलन की रणनीति तैयार की है। 27 अगस्त को हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद अब 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल बुलाई गई है। यदि मांगे नहीं मानी गईं तो तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी प्रेस क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के समक्ष बैंककर्मी जोरदार धरना-प्रदर्शन करेंगे।

मनावर में डोल ग्यारस कार्यक्रम में डीजे पर नाचने को लेकर विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

धार, मनावर। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा में डोल ग्यारस का कार्यक्रम देखने गए 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना बीती र रात करीब 1:30 बजे देवरा चौक की है। हमले में युवक का 16 वर्षीय दोस्त भी घायल हुआ है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार ग्राम अवल्दामान निवासी विकास पिता विजय किराडे (18) अपने दोस्तों प्रभांश उर्फ बिट्टू डोडवे (16), सावन धार्वे (16) और कान्हा चौहान के साथ मंगलवार रात करीब 9 बजे ग्राम देवरा में डोल ग्यारस का कार्यक्रम देखने गया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक डीजे पर नाच रहे थे। रात करीब 1:30 बजे पीली टी-शर्ट पहने एक युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया।

पेट से निकल रहा था खून

बताया गया कि विवाद के दौरान पीली टी-शर्ट पहना युवक अपने साथियों के साथ उस दिशा में भागा, जहां विकास खड़ा था। इसी दौरान विकास अचानक जमीन पर गिर गया। दोस्तों ने पास जाकर देखा तो उसके पेट से खून निकल रहा था। उसके पेट पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इसी दौरान सावन की पीठ पर भी धारदार हथियार से चोट के निशान मिले।

विवाद में शामिल युवकों की तलाश

दोस्त विकास और सावन को मोटरसाइकिल से सिविल अस्पताल मनावर लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद विकास को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल सावन को उपचार के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मनावर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 118(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस घटना के दौरान मौजूद लोगों और विवाद में शामिल युवकों की जानकारी जुटा रही है।

मध्यप्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। देश के हृदय स्थल में स्थित मध्यप्रदेश को अपने केंद्रीय भौगोलिक स्थान, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरप्लस बिजली का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त है। राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि विगत पौने तीन वर्षों में लगभग सभी सेक्टरों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्य की धरती पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात बेंगलुरु में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल बैठक में निवेशकों से संवाद के दौरान कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय को सही अवसर पर पहचान कर निर्णय लेना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। दिल्ली और मुंबई के रोड-शो में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद से स्पष्ट है कि उद्योग जगत का भरोसा मध्यप्रदेश पर निरंतर मजबूत हुआ है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश करने का यही सही समय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश शासन ने मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में एक नया और ऐतिहासिक मॉडल स्थापित किया है। ग्वालियर में बन रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसी साझी सोच का प्रतिफल है।उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में भूमि सीमित है, इसलिए ह्यपहले आओ-पहले पाओह्न के आधार पर आने वाले निवेशकों को विशेष लाभ मिलेगा, जबकि आगामी चरणों में नियम व शर्तें भिन्न होंगी। इस औद्योगिक पार्क में एक ही स्थान पर डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी वैल्यू चेन का निर्माण होगा। यहां सिम से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपकरण, 5-जी और 6-जी के उपकरण, ऑप्टिकल फायबर और आईओटी से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के औद्योगिक पार्कों की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि धार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव 2025 पर 2,000 एकड़ के ह्यपीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कह्न का भूमिपूजन हुआ था और उसी दौरान पार्क का एक-एक प्लॉट बुक हो गया। इसी प्रकार मोहासा-बाबई में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क पहले, दूसरे और तीसरे चरण पूरी तरह बुक होने के बाद अब चौथे चरण पर कार्य शुरू हो चुका है। पीथमपुर, अवंतिका और विक्रम उद्योगपुरी जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों का भारी विश्वास देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 9 महीनों में ही रक्षा से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, ट्रांसफॉर्मर से टेलीकॉम तक, हेल्थकेयर से लेकर लाइफकेयर तक, टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ऑप्टिकल फायबर केबल्स से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण से लेकर रेलवे और भारी वाहनों के निर्माण तक मध्यप्रदेश में लगभग 15 विनिर्माण इकाइयां लगी हैं।उन्होंने

मुख्यमंत्री-स्टार्टअप संवाद 27 सितम्बर को भोपाल में

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार 27 सितम्बर 2026 को आरसीवीपी नरोन्हा अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल में मुख्यमंत्री स्टार्टअप संवाद के तहत युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। संवाद में प्रदेश से लगभग 200 स्टार्टअप संचालक सम्मिलित होंगे।

एमएसएमई आयुक्त श्री कुमार पुरषोत्तम ने मंगलवार को वी सी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से अपने जिले के नव उद्यमियों को संवाद में सहभागिता करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिंदुवार समीक्षा की। स्टार्टअप संवाद में मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के युवा, नवाचारी एवं उभरते हुए स्टार्टअप उद्यमियों से सीधे संवाद करेंगे।

यह संवाद प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवाओं की उद्यमशील सोच, नवाचार तथा रोजगार सृजन की संभावनाओं को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ स्टार्टअप संस्थापकों को अपने अनुभव, उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। एमएसएमई विभाग ने स्टार्टअप संचालकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी कर सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिये बनेगी कमेटी

भोपाल। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रमाणित एवं हाइब्रिड बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कार्य-योजना पर चर्चा की गई।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि दलहन के बीजों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाना होगा। जिस प्रकार पिछले वर्ष 5 बीजों पर बीज संघ ने काम किया था, उसी प्रकार इस वर्ष कार्य-योजना बनाई जाये। दूसरे विभागों से क्या अपेक्षाएँ हैं उस पर एक पीपीटी तैयार करें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बनाकर उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने और इसके लिये अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की जाये। हाई लेवल कमेटी में सहकारिता, कृषि, उद्यानिकी और कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी शामिल हों, जो एक माह में विस्तृत रूप से कार्य कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में बीज उत्पादन एवं विपणन में शासकीय संस्थानों की उपादेयता, प्रमुख फसलों की बीज आवश्यकता, उपलब्धता, प्रदेश में प्रमुख फसलों का बोया गया क्षेत्रफल, फसलवार अधिक व कम उत्पादकता वाले जिले, हाइब्रिड बीज-आवश्यकता, शासकीय योगदान एवं कार्य-योजना, आगामी 5 वर्षों के लिये बीज उत्पादन कार्यक्रम, उद्यानिकी हाईब्रिड बीजों के लिये आधारभूत संरचना विकसित करने, बीज उत्पादन एवं विपणन में वर्तमान बाधाएँ एवं समाधान जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

प्रदेश में 25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

भोपाल। मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुलभ, सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी ह्यमुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवाह्न का 25 सितंबर 2026 को शुभारंभ होगा। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरूआती चरण में 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाना और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1500 बसें चलना शुरू हो जाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान 351 बसों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें 120 इंटरसिटी बसें हैं। ये बसें दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को सुगम और तीव्र बनाएंगी। 231 इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल है।

इंदौर में 145 बस, जिसमें 50 इंटरसिटी, 95 इंट्रासिटी, भोपाल के लिए 106 बसें, जिसमें 23 इंटरसिटी, 83 इंट्रासिटी, जबलपुर के लिए 67 बसें, जिसमें 14 इंटरसिटी, 53 इंट्रासिटी। रीवा की 18 इंटरसिटी बस, देवास की 10 इंटरसिटी बस, कटनी की 3 और भिंड की 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

70 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को हरित धरोहर घोषित करने की मांग, इनके पास से हटें पेवर ब्लॉक

इंदौर। इंदौर शहर की पहचान सिर्फ सड़कों, इमारतों और बाजारों से नहीं बल्कि वर्षों पुराने पेड़ों, कुएं-बावड़ियों और तालाबों से भी होती है। तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण के बीच अब इस प्राकृतिक विरासत को बचाने की आवाज उठने लगी है। पर्यावरण प्रेमी मंच ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर के पुराने पेड़ों और जलस्रोतों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की है।

मंच ने 70 से 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेड़ों को ह्यहरित धरोहरह्न घोषित करने पर जोर दिया है। ऐसे पेड़ों की पहचान कर उनकी जियो-टैगिंग की जाए और उनका अलग से ग्रीन हेरिटेज रजिस्टर बनाया जाए। इससे इन पेड़ों की जानकारी सरकारी रिकार्ड में सुरक्षित रहेगी और भविष्य में किसी विकास कार्य के दौरान उन्हें बचाने की योजना पहले से बनाई जा सकेगी।

पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों के आसपास किए गए सीमेंटीकरण और पेवरीकरण को हटाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि जब पेड़ों के तने और जड़ों के आसपास पूरी जमीन पक्की कर दी जाती है तो वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता। इससे पेड़ कमजोर होते हैं और भूजल रिचार्ज भी प्रभावित होता है। पुराने और अनुपयुक्त ट्री-गार्ड भी हटाए जाने चाहिए ताकि पेड़ों को पर्याप्त जगह और पानी मिल सके।

विकल्प तलाशे जाएं

ज्ञापन में हुकुमचंद मिल, एमओजी लाइंस, मेट्रो, नया आयुर्वेदिक कॉलेज, न्यू एमवाय अस्पताल, मास्टर प्लान की सड़कें, रानी सराय, नया रेलवे स्टेशन और शास्त्री पुल सहित परियोजनाओं में ह्यपहले पेड़ बचाएंह्न नीति लागू करने की मांग की गई है। मंच का कहना है कि किसी पेड़ को काटने से पहले डिजाइन या सड़क के अलाइनमेंट में बदलाव सहित सभी विकल्प तलाशे जाएं और कटाई को अंतिम विकल्प रखा जाए। साथ ही शहर के करीब 500 कुएं-बावड़ियों और 20 तालाबों का सीमांकन, जियो-टैगिंग, सफाई और अतिक्रमण हटाकर पुनर्जीवन की मांग की गई है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।